A–BRL–M–MBXA

विधि

प्रश्न-पत्र—I

LAW

Paper—I

समय : तीन घंटे
Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250
Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कुल आठ (8) प्रश्न दो खण्डों में दिए गए हैं तथा वह हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे हुये हैं।

परीक्षार्थी को कुल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न क्रमांक 1 एवं 5 अनिवार्य हैं। शेष प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न चुनते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक प्रश्न के अंत में सूचित हैं।

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में उत्तर लिखना आवश्यक है तथा यह क्यूसीए (Question-cum-Answer) पुस्तिका में निर्दिष्ट जगह पर उल्लेख करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गये उत्तरों को अंक नहीं दिये जायेंगे।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किये गये शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तर क्रमिक विन्यास में गिने जायेंगे। नहीं काटे गए प्रश्न के उत्तर को भी गिनती में लिया जायेगा यद्यपि उसके उत्तर आंशिक रूप में दिए गए हों। उत्तर-पुस्तिका में कोई पन्ना या पन्ना के अंश अगर खाली हैं तो उसे/उन्हें स्पष्ट रूप से काट देना जरूरी है।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are **EIGHT** questions divided in **Two Sections** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Question no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in chronological order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

खण्ड—अ

SECTION—A

Q.1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए) :—

Answer the following (each answer should be in about 150 words) :— 10×5=50

Q. 1(a) निदेशक सिद्धान्तों के निर्वचन में क्या न्यायपालिका बाधक है या सहायक ? सर्वोच्च न्यायालय के विविध निर्णयन के आलोक में परीक्षण कीजिए।

Has judiciary been a hindrance or a facilitator in the interpretation of Directive Principles ? Examine in the light of various judgements of the Supreme Court. 10

Q. 1(b) "मौलिक कर्त्तव्य केवलमात्र नीतिशास्त्रीय या नैतिक कर्त्तव्य हैं एवं इन्हें मौलिक नियम का एक अंग नहीं बनना चाहिए।" टिप्पणी कीजिए।

"Fundamental duties are only ethical or moral duties and should not form a part of the fundamental law." Comment. 10

Q. 1(c) क्या 'वाणिज्यिक विज्ञापन' 'भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की परिधि के अंतर्गत समाविष्ट है ? मुख्य मुकदमों की सन्दर्भसहित चर्चा कीजिए।

Is 'Commercial advertisement' covered within the ambit of 'freedom of speech and expression' ? Discuss with reference to leading cases. 10

Q. 1(d) धारा 16(4) को हटाने के संशोधन एवं समाज के पिछड़े वर्ग को सेवाओं में आरक्षण देने का नियम बनाने के लिये राज्य को प्राधिकृत करने की संवैधानिक आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

Critically examine the constitutional validity of an amendment deleting Article 16(4) and authorising the State to make job reservation in favour of the backward classes of citizens. 10

Q. 1(e) संविधान के अधीन समानता का सिद्धांत एक गैर-कानूनी कार्य को वैध ठहराने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या अन्य नीतिविरुद्ध को औचित्यपूर्ण करने के लिए समानता की सहायता ली जा सकती है ? वादों के सन्दर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Doctrine of equality under the Constitution cannot be applied to legitimise an illegal act. Can equality be invoked to justify another wrong ? Critically examine with reference to cases. 10

Q. 2(a) क्या आप इस मत से सहमत हैं कि "समानता स्वेच्छा का वैपरीत्य है ? वास्तव में समानता एवं स्वेच्छाचारिता अधिष्ठित दुश्मन हैं" ? आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।

Do you agree with the view that "Equality is antithesis of arbitrariness. In fact equality and arbitrariness are sworn enemies" ? Comment critically. 25

Q. 2(b) "भारतीय संविधान केवल शासकीय कार्यकलापों के त्रि-विभाग में विभाजन का स्वाक्षर करता है एवं इसके सार्वभौमिक कठोरता में अधिकार पृथक्करण के सिद्धांत में नहीं।" टिप्पणी कीजिए।

"The Constitution of India merely subscribes to three-fold division of gubernatorial functions and not to the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity." Comment. 25

Q. 3(a) प्रस्तावना (भूमिका) में विनिर्दिष्ट लक्ष्य हमारे संविधान की मौलिक संरचना में अन्तर्भुक्त हैं जिनका धारा 368 के अधीन संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रमुख वादों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कीजिए।

The goals specified in the Preamble contain basic structure of our Constitution, which cannot be amended under Article 368. Elaborate in context of leading cases. 25

Q. 3(b) आपातकाल की सरकारी घोषणा के दुष्प्रयोग को रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन (44th) द्वारा कौनसी निर्बंधनों का प्रावधान किया गया है ? चर्चा कीजिए।

What restrictions have been imposed by the Constitutional Amendment (44th) to check misuse of proclamation of emergency ? Discuss. 25

Q. 4. निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखिए :—

Write critical notes on the following :— **50**

Q. 4(a) अवशिष्ट अधिकार।

Residuary Powers. 15

Q. 4(b) क्या धारा 19 के उल्लंघन हेतु निवारक निरोध से सम्बन्धित नियम को चुनौती दी जा सकती है ?

Whether law relating to preventive detention can be challenged for violation of Article 19 ? 15

Q. 4(c) समान सिविल संहिता की पुर:स्थापना।

Introduction of Uniform Civil Code. 20

खण्ड—ब

SECTION—B

Q. 5(a) "अन्तर्राष्ट्रीय वैधिक नियमों का घरेलू विधियों में बढ़ते हुए अनुगमन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय एवं नगरपालिका कानून के दो स्वायत्व क्षेत्रों के बीच व्यवस्थित विशिष्टता कुछ हद तक दुर्बोध्य हो गई।" भारतीय पद्धति के विशेष सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए। प्रथा एवं सन्धियों से उद्भूत अन्तर्राष्ट्रीय वैधिक नियम कैसे घरेलू एजेन्सियों के कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं ?

"Due to increasing penetration of international legal rules within the domestic systems, the distinction maintained between two autonomous zones of international and municipal law has been somewhat blurred."

Explain with special reference to Indian practice. How international legal rules emanating from customs and treaties, influence the actions of domestic agencies ? 10

Q. 5(b) बहुपार्श्वीय संधि समापन करते समय एक राष्ट्र कुछ प्रतिबंध (शर्त) रख सकता है तथा अन्य राष्ट्र उन शर्त/शर्तों को, संधि के उद्देश्य एवं अखण्डता को किसी प्रकार विपन्नता में डाले बिना स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में संधि कानून में प्रतिबंध की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए।

While concluding a multilateral treaty, a State can make reservation(s) and the other State(s) may accept or reject such reservation(s) without jeopardising the object and integrity of the treaty.

Discuss the need and relevance of reservations in treaty law in the light of above statement. 10

Q. 5(c) महाद्वीपीय शेल्फ, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एवं खुला सागर पर तटीय राष्ट्र के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को जैसे समुद्र के कानून (III), 1982 पर राष्ट्रसंघ अभिसमय के प्रावधानों के अधीन परिभाषित है, समझाइये।

Explain the rights and duties of coastal state over continental shelf, exclusive economic zone and high seas as defined under the provisions of UN Convention on Law of Sea (III), 1982. 10

Q. 5(d) मत संख्या 2 (Opinion No. 2) में, यूगोस्लाविया पर "The Arbitration Commission of European Conference" ने स्पष्ट शब्दों में ये उच्चारण किया कि "यह भली-भांति प्रतिष्ठित है कि परिस्थिति जैसी भी हो, स्व-निर्धारण के अधिकार में, 'स्वतन्त्रता प्राप्तिकाल में विद्यमान सीमान्त प्रदेशों में किसी प्रकार के परिवर्तन' शामिल नहीं होंगे (Uti possidetis juris) सिवाय (व्यतिक्रम) यह कि संश्लिष्ट राष्ट्र अन्यथा (पक्षांतर) एकमत हों।"

कम से कम एक प्रकृत घटना (नजीर) की सहायता से उभय अन्तर्राष्ट्रीय संविदाओं में अन्तर्भुक्त मानव अधिकार के रूप में स्व-निर्धारण के सिद्धान्त की वर्तमानकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए।

The Arbitration Commission of European Conference on Yugoslavia emphasised in opinion no. 2 that "it is well established that whatever the circumstances, the right to self-determination must not involve changes to existing frontiers at the time of independence (Uti possidetis juris) except where the states concerned agree otherwise."

Explain the present day relevance of principle of self-determination as a human right incorporated in both the international covenants with the help of at least one actual instance. 10

Q. 5(e) "किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे देश से जिससे उसका प्रमापिक संबंध नहीं है, प्राप्त नागरिकता को मान्यता देने के लिए कोई राज्य बाध्य नहीं होते।"

[Nottebohm case (second phase) ICJ, 1955]

उपरोक्त कथन के संदर्भ में "राष्ट्रीयता" की अवधारणा एवं इसके अर्जन को उपयुक्त घटनाओं की सहायता से समझाइये।

"States are not under a duty to recognize a nationality acquired by a person who has no genuine link or connection with the naturalizing state."

[Nottebohm case (second phase) ICJ, 1955]

In the light of above statement, explain the concept of 'nationality' and its acquisition with the help of suitable instances. 10

Q. 6(a) "रूढ़िजन्य विधि के सार की जानकारी प्राथमिकत: विद्यमान पद्धति एवं राज्यों के 'opinio juris' में खोजनी चाहिए।" उपरोक्त कथन के संदर्भ में एवं वाद कानून का उल्लेख करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में एक विशिष्ट प्रथा को ग्रहण करने में वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ तत्वों के बीच पारस्परिक प्रभाव को समझाइये।

"The substance of customary law must be looked into primarily in actual practice and 'opinio juris' of the States." In the light of above statement and by referring to case law, explain the interplay between objective and subjective elements in acceptance of a particular custom as a source of international law. 25

Q. 6(b) "राष्ट्रीयता के लिए वैधिक जरूरतों को सम्पादन करने वाले एक नये राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन मान्यता देने के लिए राष्ट्रसमूह कर्तव्य बाध्य है किन्तु ऐसे कर्तव्य की विद्यमानता राष्ट्रों के पूर्व नजीर एवं प्रथाओं द्वारा समर्थित नहीं होती। मान्यता देने या न देने में राष्ट्र के निर्णय अत्यावश्यक नीति का विषय है जिसको तय करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र स्वयं अधिकृत है।" न्यायसंगत (de facto) एवं कानूनन (de jure) मान्यता के सम्बन्ध में घटनाओं की सहायता से, तर्क व सामंजस्य द्वारा बताइए कि राष्ट्र की मान्यता सम्बन्धी लाउटरपैक्ट (बाध्यतामूलक) एवं पोदेस्टा कॉस्टा (दक्षतात्मक) द्वारा दिए गये इन दो कथनों (चरम मतवादों) में कौन-सा अधिक उपयुक्त है ?

"States are subject to a duty under International Law to recognise a new State fulfilling the legal requirements of Statehood, but the existence of such a duty is not borne out by the weight of precedents and practices of States. The decision of a State in according or withholding recognition is a matter of vital policy that each State is entitled to take by itself." Reconcile and argue which of these two statements (extreme views) regarding recognition of a State given by Lauterpacht (obligatory) and by Podesta Costa (Facultative) is more appropriate, with the help of instances in regard to *de facto* and *de jure* recognition.

25

Q. 7(a) अन्तर्राष्ट्रीय कानून में "आवश्यकता" एवं "अनुपातिकता" अवधारणाएं आत्म-रक्षा के केन्द्र हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर एवं 'आसन्न आक्रमण तथा शास्त्रसज्जा में उन्नति' के कारण 'अधिकारात्मक' या 'प्रत्याशी' आत्म-रक्षा में इनके विस्तारण के निकटवर्तिता प्रवृत्ति के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

The concepts of 'necessity' and 'proportionality' are at the heart of self-defence in International Law. Explain, in the light of UN Charter and recent trend of extending these to 'pre-emptive' or 'anticipatory' self-defence due to 'the imminence of attacks and advancement in armaments'.

25

Q. 7(b) तीन व्यक्तियों (L, M एवं N) का एक दल देश-A के नागरिक हैं, A के प्रमुख अन्वेषक एजेन्सी के अधिकारी के रूप में मिथ्या परिचय देकर एक विशाल ज्वैलरी दुकान में डकैती करने के बाद देश-B में पलायन करते हैं जहां उनको आश्रय दिया जाता है। देश-A की सरकार देश-B को उनके बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार L, M एवं N को प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करती है। देश-B इंकार करता है। देश-A देश-B में गुप्तचर भेजता है, जो L, M एवं N को हरण कर ले आते हैं एवं देश-A में न्यायालय के सामने उनको प्रस्तुत करते हैं। 'A' द्वारा बल प्रयोग के विरुद्ध 'B' ICJ के पास जाता है। तैयार कीजिए : (i) A के लिए संक्षिप्त तर्कावली, (ii) B के लिए संक्षिप्त तर्कावली, (iii) न्यायालय के अभिमत।

A group of three men (L, M and N) citizens of country A, posing as officers of premier investigating agency of A, rob a huge jewellery shop and then flee away to country B, where they are granted asylum. Government of A, requests B to extradite L, M and N in terms of extradition treaty between them. B declines. A sends spies to B who abduct L, M and N and who produce them before the Court in A. 'B' approaches ICJ against use of force by 'A'. Prepare (i) A brief of arguments for A, (ii) A brief of arguments for B, (iii) Opinion of the Court.

25

Q. 8(a) संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर (UN Charter) के परिच्छेद-VI अन्तर्राष्ट्रीय कलह के शांतिपूर्ण समाधानार्थ समर्पित हैं। उल्लेखित विधियों की चर्चा कीजिए एवं इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद एवं महासभा की भूमिका स्पष्ट कीजिए एवं अध्याय-VII में उल्लेखित उपायों के आश्रय लिए बिना उक्त समाधान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए।

Chapter VI of UN Charter is devoted to peaceful settlement of International Disputes. Discuss the methods mentioned and explain the role of Security Council and General Assembly in this regard, and the role such settlement plays in obviating the need to resort to Chapter VII measures. 25

Q. 8(b) यूरोपीय संघ (European Union) के एक सदस्य राष्ट्र को निम्नलिखित के बारे में प्रत्यक्ष-दर्शन हुआ है :

सेनावाहिनी द्वारा शासन व्यवस्था दखल के परिणामस्वरूप बहुविस्तारित अराजकता, सर्वप्रकार के मीडिया एवं संचार माध्यम में प्रतिबन्धकता, बहिष्कृत नेता से हमदर्दी रखनेवाले नागरिकों पर आक्रमण व उनकी हत्याएं, ईंधन (fuel) एवं खाद्य-सामग्री जैसे उपभोग्य वस्तु पर कठोर राशनिंग एवं नियंत्रण तथा इसके परिणामस्वरूप प्रचण्ड मुद्रास्फीति। मानव अधिकार के इन गंभीर उल्लंघनों के संदर्भ में निम्नोक्त की भूमिका का परीक्षण कीजिए :

(i) सुरक्षा परिषद

(ii) मानव अधिकार के यूरोपीय न्यायालय।

A member of European Union has witnessed widespread disturbances, consequent upon a military *coup*, including censorship on all forms of media and communication, targeting civilians sympathetic with the ousted leader by assaulting and killing, severe rationing and control on essential commodities such as fuel and food resulting into galloping inflation. In the light of these grave violations of human rights, examine the role of :

(i) Security Council

(ii) European Court of Human Rights. 25

CS (Main) Exam : 2014 वियोज्य DETACHABLE

विधि (प्रश्नपत्र I)

292

LAW (Paper I)

समय : तीन घण्टे Time Allowed : Three Hours	अधिकतम अंक : 250 Maximum Marks : 250

प्रश्नपत्र सम्बन्धी अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

कुल **आठ (8)** प्रश्न दो **खंडों** में दिए गए हैं तथा वह **हिन्दी** एवं **अंग्रेजी** दोनों भाषाओं में छपे हुये हैं ।

परीक्षार्थी को कुल **पांच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न क्रमांक **1** एवं **5** अनिवार्य हैं । शेष प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम से कम **एक** प्रश्न चुनते हुए **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक प्रश्न के अंत में सूचित हैं ।

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में उत्तर लिखना आवश्यक है तथा यह क्यूसीए (Question-cum-Answer) पुस्तिका में निर्दिष्ट जगह पर उल्लेख करना आवश्यक है । प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गये उत्तरों को अंक नहीं दिये जायेंगे ।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किये गये शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तर क्रमिक विन्यास में गिने जायेंगे । नहीं काटे गए प्रश्न के उत्तर को भी गिनती में लिया जायेगा यद्यपि उसके उत्तर आंशिक रूप में दिए गए हों । उत्तर-पुस्तिका में कोई पन्ना या पन्ना के अंश अगर खाली हैं तो उसे/उन्हें स्पष्ट रूप से काट देना जरूरी है ।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are EIGHT questions divided into two SECTIONS and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question No. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE from each section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in chronological order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

खण्ड 'A' SECTION 'A'

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में होने चाहिए :
Answer the following (each answer should be in about 150 words) :

1.(a) आपके विचार में हमारे संविधान का स्वरूप/प्रकृति क्या है — परिसंघीय, ऐकिक अथवा अर्ध-परिसंघीय ? प्रारूपण समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के सदस्यों ने इसको परिसंघीय कहा है, परंतु अनेक अन्य इस अभिधान (टाइटल) का प्रतिवाद करेंगे । इस कथन का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए ।
What do you think is the form/nature of our Constitution — Federal, Unitary or Quasi-federal ? The Members of the Drafting Committee call it federal, but many others would dispute this title. Critically examine the statement. 10

1.(b) 'संवैधानिकता' से क्या तात्पर्य है ? 'संवैधानिकता' से भारत की परियुक्ति (ट्राइस्ट) और 'संवैधानिक शासन' के संदर्भ में, इस संकल्पना को, इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों में, स्पष्ट कीजिए ।
What is 'Constitutionalism' ? Explain the said concept both in its negative and positive aspects in the context of India's tryst with 'Constitutionalism' and 'Constitutional Governance'. 10

1.(c) अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को, और विशेषकर उच्चतम न्यायालय को, मूल अधिकारों का संरक्षक, संरक्षी और निर्वचक बनाता है । यदि कोई विधि मूल अधिकार के असंगत हो, तो यह न्यायालयों को उस विधि को 'शून्य' (वौएड) घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है और साथ ही साथ ऐसा करने की बाध्यता अधिरोपित करता है । चर्चा कीजिए ।
Article 13 makes the judiciary, and especially the Apex Court, as a guardian, protector and the interpreter of the Fundamental Rights. It confers a power as well as imposes an obligation on the Courts to declare a law void if it is inconsistent with a Fundamental Right. Discuss. 10

1.(d) उच्चतम न्यायालय की 'विशेष इजाज़त अधिकारिता' की व्याप्ति को, जैसे कि उसने इसको प्रतिपादित किया है, स्पष्ट कीजिए ।
Explain the scope of the 'Special Leave Jurisdiction' of the Supreme Court as expounded by it. 10

1.(e) 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए । साथ ही भारत में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए ।
Examine the doctrine of separation of powers. Also mention the relevance of this doctrine in India. 10

2.(a) 'उचित अवसर' की संकल्पना के 'पदावधि प्रसादपर्यन्त' के सिद्धांत पर एक संवैधानिक परिसीमा होने के नाते, संसद या राज्य विधान-मंडल 'उचित अवसर' की विषय-वस्तु की परिभाषा करते हुए और अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को कथित अवसर प्रदान करने की कार्यविधि निर्धारित करते हुए, एक विधि का निर्माण कर सकता है । अग्रनिर्णयों का उल्लेख करते हुए इस संकल्पना को स्पष्ट कीजिए ।
The concept of 'Reasonable Opportunity' being a constitutional limitation on the doctrine of 'Tenure Pleasure', Parliament or State Legislature can make a law defining the content of 'Reasonable Opportunity' and prescribing procedure for affording the said opportunity to the accused government servant. Explain the concept with reference to leading cases. 20

2.(b) 'दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार' के अर्थ को, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने पापानाशम श्रमिक संघ बनाम मदुरा कोट लिमिटेड (ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 2200) में उसका निर्वचन किया है, स्पष्ट कीजिए और पूरी तरह समझाइए । इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिए ।
Explain and elucidate the meaning of the 'Right to personal liberty' as interpreted by the Supreme Court in Papanasam Labour Union v. Madura Coat Ltd. AIR 1995 S.C. 2200. Analyse critically the guidelines prescribed by the Hon'ble Supreme Court in this respect. 15

2.(c) शब्द 'लोक सेवक' की परिभाषा कीजिए । साथ ही भारत में लोक सेवकों की भर्ती की कार्यविधि पर चर्चा कीजिए ।
Define the term 'public servant'. Also discuss the recruitment procedure of public servants in India. 15

3.(a) भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालों की अध्यादेश-निर्माण-शक्ति की संवैधानिक व्याप्ति का परीक्षण कीजिए और सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।
Examine and elucidate the constitutional scope of the Ordinance making power of the President and the Governors in India. 20

3.(b) किसी पिछड़े वर्ग की पहचान केवल और अनन्य रूप से आर्थिक कसौटी के प्रमाण पर नहीं की जा सकती है । परंतु फिर भी, पिछड़ी जाति की पहचान व्यवसाय-व-आय के आधार पर, जाति की ओर देख बिना ही, की जा सकती है । राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को 'पिछड़ा' और 'अधिक पिछड़ा' के रूप में श्रेणीबद्ध करने पर कोई संवैधानिक पाबंदी नहीं है । क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण बताइए ।

A backward class cannot be identified only and exclusively with reference to economic criterion. A backward class may, however, be identified on the basis of occupation-cum-income without any reference to caste. There is no constitutional bar in the State categorising the backward classes as 'backward' and 'more backward'. Do you agree with the statement ? Give reasons. 15

3.(c) 'लोक हित मुकदमेबाजी' से क्या तात्पर्य है ? मुकदमेबाजी के इस रूप के क्या प्रमुख पक्ष हैं ? साथ ही इस प्रकार की मुकदमेबाजी की परिसीमाओं पर चर्चा कीजिए।
What is 'Public Interest Litigation' ? What are the major facets of this form of litigation ? Also discuss the limitations of this type of litigation. 15

4.(a) 'संविधानी शक्ति', 'संशोधनकारी शक्ति' और 'विधायी शक्ति' की परिभाषा कीजिए और उनके बीच विभेदन कीजिए। उदाहरण पेश कीजिए।
Define and distinguish between 'Constituent power', 'Amending power' and 'Legislative power'. Give illustrations. 20

4.(b) क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "सभी मानव अधिकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित और मान्यताप्राप्त मूल अधिकार हैं।" कानूनी उपबंधों और निर्णयजन्य विधि का उल्लेख करते हुए, इस पर चर्चा कीजिए।
Do you agree with the statement that "all human rights are fundamental rights protected and recognised by the Constitution of India". Discuss with reference to statutory provisions and case laws. 15

4.(c) जैसे कि वे भारत के संविधान में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य गिनाइए। साथ ही, कालांतर में भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किए जाने के पीछे के तर्काधार पर चर्चा कीजिए।
Enumerate the fundamental duties as provided in the Constitution of India. Also discuss the rationale behind the incorporation of fundamental duties in the Constitution of India later on. 15

खण्ड 'B' SECTION 'B'

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में हों :
Answer the following (each answer should be in about 150 words) :

5.(a) अंतर्राष्ट्रीय विधि के आरंभ को चिह्नित करने के लिए इतिहास में किसी परिशुद्ध तारीख या काल को नियत करना असंभव है क्योंकि आरंभ रिकार्ड किए इतिहास से पूर्व का है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय समाज में अंतर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास, प्रकृति, व्याप्ति और प्रांसगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
It is impossible to fix a precise date or period in history to mark the beginning of International Law as it predates recorded history. Critically examine the history, nature, scope and relevance of International Law in Contemporary International Society. 10

5.(b) किसी राज्य द्वारा घमंडवश अधिकारिता (ज्यूरिसडिक्शन) स्वतः ग्रहण कर लेने पर भी, अंतर्राष्ट्रीय विधि उस पर अत्यंत कम या शून्य परिसीमा नियत करती है। 'राज्य अधिकारिता' की प्रकृति और व्याप्ति (स्कोप) स्पष्ट कीजिए। 'राज्य-अधिकारिता' के सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए।
International Law sets little or no limitation on the jurisdiction which a particular State may arrogate to itself. Explain the nature and scope of 'State Jurisdiction'. Critically examine the principles of 'State Jurisdiction'. 10

5.(c) "मान्यता मांगने वाली सत्ता पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन मान्यता मिल जाना उस सत्ता को राज्य की विधिक हैसियत प्रदान कर देती है। मान्यता से महत्वपूर्ण विधिक प्रभाव प्राप्त किये जा रहे हैं।" इस कथन का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए।
Recognition confers the legal status of a State under International Law upon the entity seeking recognition. Important legal effects are being derived from recognition. Critically examine the statement. 10

5.(d) अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्यों या राज्य संगठनों के बीच संविदात्मक प्रकृति के करार होते हैं, जो पक्षों के बीच विधिक अधिकारों और बाध्यताओं (ऑब्लिगेशन्स) को जन्म देते हैं। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों के बढ़ते हुए महत्व को स्पष्ट कीजिए।
International Treaties are agreement of contractual character between States or organisation of States creating legal rights and obligations between the parties. Examine the statement critically and explain the growing importance of Treaties in Modern International Law. 10

5.(e) आप संकल्पना 'राजनयिक उन्मुक्ति' से क्या समझते हैं ? इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन क्या प्रावधान प्रदान किए गए हैं ? चर्चा कीजिए ।
What do you understand by the concept 'Diplomatic Immunity'. What rules are provided under International Law in this respect. Discuss. 10

6.(a) 'अंतर्राष्ट्रीय मानवहितवादी विधि' की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए । इसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवहितवादी विधि के विकास में 'हेग' और 'जेनेवा' अभिसमयो (कनवेंशन्स) की भूमिका का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए ।
Explain the concept of 'International Humanitarian Law'. How can it be achieved ? Critically examine the role of 'The Hague' and 'The Geneva Convention' in the development of Modern International Humanitarian Law. 20

6.(b) "अनेक पहलुओं में 'ट्रिप्स' करार पारंपरिक 'गैट' उपागम से आगे निकल जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विधि का और ज्यादा विकास करता है ।" बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पक्षों पर करारों (ट्रिप्स) की महत्वपूर्ण उपलब्धि की परीक्षा कीजिए ।
'In several respects the TRIPS Agreement goes beyond the traditional GATT approach and further develops the law of International Trade'. Examine the important achievement of the Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. (TRIPS). 15

6.(c) 'मत्स्य क्षेत्र' से क्या तात्पर्य है ? यह 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' से किस प्रकार भिन्न है ? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'तटवर्ती राज्य की अपने भूभागीय समुद्र के निकट महासमुद्र (हाई सी) के किसी भी क्षेत्र में जीवित संसाधनों की उत्पादकता के अनुरक्षण में विशेष रुचि होती है' । सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।
What is 'fishery zone' ? How it is different from 'Exclusive Economic Zone' ? Do you agree with the statement that 'a coastal state has a special interest in the maintenance of the productivity of the living resources in any area of the high seas adjacent to its territorial sea'. Elucidate. 15

7.(a) 'विश्व व्यापार संगठन' के उद्देश्य, संरचना और प्रकार्यण क्या हैं ? क्या डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर करना और अनुसमर्थन करना (रैटिफाइंग) भारत की संसदीय स्वायत्तता को क्षति पहुँचाता है ? चर्चा कीजिए ।
What are the objectives, structure and functioning of World Trade Organisation ? Does signing and ratifying WTO undermine the Parliamentary Autonomy of India ? Discuss. 20

7.(b) वायुक्षेत्र (एयर स्पेस) पर संप्रभुता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के उपयोग और दुरुपयोग के विधिक नियंत्रण की गुंजाइश का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
Trace the development of International Law relating to sovereignty over air-space. Critically examine the scope of legal control of use and abuse of outer space. 15

7.(c) 'मध्यक्षेप' (इंटरवैन्शन) की परिभाषा कीजिए और उन आधारों का उल्लेख कीजिए जिनके अधीन यह न्यायोचित होता है । अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस सिद्धांत के उल्लंघनों पर भी प्रकाश डालिए ।
Define intervention and mention the grounds under which it is justified. Also throw light on the violations of this principle of International Law. 15

8.(a) "जब प्रत्यर्पण (ऐक्स्ट्राडीशन) आरंभ हो जाता है, तब शरण (ऐसाइलम) को विराम लगता है ।" टिप्पणी कीजिए । साथ ही अग्रणी केसों के उल्लेख के साथ प्रत्यर्पण के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए ।
"Asylum stops as it were when extradition begins". Comment. Also explain the various principles of extradition with reference to leading cases. 20

8.(b) अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि (म्यूनिसिपल लौ) के बीच संबंध के संदर्भ में, विरुद्धता (अपोज़ेबिलिटी) की संकल्पना की परिभाषा कीजिए । साथ ही, भारत के विशेष उल्लेख के साथ, आधुनिक काल में, इस संकल्पना की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए ।
Define the concept of 'opposability' in the context of relationship between International Law and Municipal Law. Also discuss the relevance of this concept in modern times with special reference to India. 15

8.(c) समुद्र की विधि पर सं.रा. (यू.एन.) अभिसमय 1982 के अधीन 'बेस लाइन' का क्या महत्व और अर्थ है ? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?
What is the importance and meaning of 'Base Line' under UN convention on Law of Sea 1982 ? How is it determined ? 15

CS (Main) Exam 2015

C-AVZ-O-MBXA

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : **तीन** घंटे Time Allowed : **Three** Hours	अधिकतम अंक : **250** Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

*इसमें आठ प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं ।*

*परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।*

*प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

*There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

*Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.*

*Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each section.*

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए :
Answer the following in about 150 words each : *10×5=50*

(a) समकालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं को देखते हुए, अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए, कोई अभिकरण/निकाय 'राज्य' है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए विकसित न्यायिक ढाँचे का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । क्या यह परीक्षण आजकल अत्यधिक संकीर्ण है ? अपने उत्तर के पक्ष में दलील दीजिए ।

Given the contemporary economic, political and social realities, critically evaluate the judicial framework developed to determine whether an agency/body is 'State' for the purposes of Article 12. Is the test currently too narrow ? Justify your answer. *10*

(b) इस मत के बारे में आपका क्या विचार है कि अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा दया प्रदान करने की शक्तियों का उपयोग भी सांविधानिक चुनौती के लिए खुला होना चाहिए ? देश के उच्चतम न्यायालय के हाल के केसों का उल्लेख करते हुए इस पर चर्चा कीजिए ।

What would be your opinion regarding the view that the exercise of powers by the President and Governors under Article 72 and 161 to grant mercy should also be open to Constitutional Challenge ? Discuss with reference to recent cases of the Apex Court of the country. *10*

(c) "भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है लेकिन उचित वर्गीकरण को नहीं मना करता है ।" परीक्षण कीजिए और साथ में चर्चा कीजिए कि इस सांविधानिक उपबंध के द्वारा प्रस्थिति और अवसर की समानता किस हद तक प्राप्त की जाती है ।

"Article 14 of the Constitution of India forbids class legislation not reasonable classification." Examine and also discuss how far equality of status and opportunity are achieved by this Constitutional provision. *10*

(d) भारत के संदर्भ में 'लोकायुक्त' और 'लोकपाल' शब्दों को परिभाषित कीजिए और उनके बीच विभेद कीजिए । साथ ही, इसकी प्रासंगिकता का भी उल्लेख कीजिए ।

Define and distinguish between the terms 'Lokayukta' and 'Lokpal' in the Indian context. Also mention about its relevance. *10*

(e) अभिव्यंजना 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' से आप क्या समझते हैं ? क्या कारण है कि आजकल इस पर चर्चा/वाद-विवाद/प्रश्न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ? इस गतिविधि के लिए आप कौन-से कारण बताएँगे ? *10*

What do you understand by the expression 'independence of judiciary' ? Why is it being discussed/debated/questioned too much nowadays ? What reasons would you give for this development ?

Q2. (a) " 'जीवन का अधिकार' का अर्थ केवल प्राणि-अस्तित्व से कुछ अधिक होता है ।" केस विधि के उल्लेख के द्वारा इस पर चर्चा कीजिए । क्या अभिव्यंजना 'जीवन का अधिकार' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के बीच कोई अंतर है ? समालोचनापूर्वक स्पष्ट कीजिए ।

"Right to life means something more than mere animal existence." Discuss with reference to case law. Is there any difference between the expression 'right to life' and 'personal liberty' ? Explain critically. *20*

(b) "प्रधान मंत्री मंत्रिमंडल मेहराब का सर्वप्रमुख पत्थर होता है क्योंकि वही उसकी रचना, जीवन और मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार होता है ।" संविधान के विभिन्न उपबंधों के प्रकाश में उपर्युक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और मंत्रिमंडल में भारत के प्रधान मंत्री की स्थिति का निर्धारण कीजिए ।

"The Prime Minister is the keystone of the Cabinet arch because he is responsible for its formation, life and death." Critically examine the above statement in the light of various provisions of the Constitution and determine the position of the Prime Minister of India in the Cabinet. *15*

(c) 'विधिक सहायता' के क्षितिज का विस्तार हो गया है, परंतु फिर भी अभी तक उसका प्रभाव पूरी तरह दिखाई नहीं देता है । आप इस संकट को किस प्रकार सुलझाएँगे, जो हमारे देश के करोड़ों ग़रीबों के जीवन को सालों-सालों से बर्बाद कर रहा है । इसको अधिक प्रभावी और कार्यान्वयन-क्षम बनाने के लिए कुछ ठोस उपाय सुझाइए ।

The horizon of 'Legal aid' has been widened best, still the impact is totally missing. How would you resolve this crisis which is ruining the life of millions of poor people of our country over the years ? Suggest some concrete measures to make it more effective and implementative. *15*

Q3. (a) इस तथ्य के प्रकाश में कि भारत के संविधान में प्रत्यायोजित विधान पर कोई व्यक्त प्रतिषेध नहीं है, अत्यधिक प्रत्यायोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए या सांविधानिक परिसीमाओं के बिना प्रत्यायोजन की अनुमति प्रदान करते हुए, अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोणों के आधार का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

In light of the fact that the Constitution of India has no express prohibition on delegated legislation, critically evaluate the basis for different judicial positions either prohibiting excessive delegation or permitting delegation without Constitutional limitations. *20*

(b) 'संरक्षित विभेद' क्या होता है ? परीक्षण कीजिए कि अनुच्छेद 15 और 16 के अधीन यह किस सीमा तक सांविधानिक है । विनिश्चित केसों का उल्लेख कीजिए । इसके साथ, जहाँ तक इसके अनुप्रयोग का प्रश्न है, इन अनुच्छेदों की परिसीमाओं का उल्लेख कीजिए ।

What is 'Protected discrimination' ? Examine how far it is constitutional under Article 15 and 16. Give reference of decided cases. Also mention the limitations of these articles as per its application. *15*

(c) "सूचियों के बीच अपरिहार्य और अनमेल विरोध के मामले में, अनुच्छेद 246 में सर्वोपरि खंड को अंतिम साधन माना जाना चाहिए ।" समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए । साथ ही, इस खंड से संबंधित दुरुपयोग/दुरुपयोगों पर चर्चा कीजिए । क्या 'तत्त्व और सार के सिद्धांत' और 'सर्वोपरि खंड' के बीच कोई संबंध है ?

"The non-obstante clause in Article 246 ought to be regarded as last resource in case of an inevitable and irreconcilable conflict between the lists." Examine critically. Also discuss the abuse/abuses related to this clause. Is there any connection between the doctrine of 'pith and substance' and 'non-obstante clause' ? *15*

Q4. (a) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए, संबंधित पक्षों के अतिरिक्त, किन परिस्थितियों में, अन्य व्यक्ति का सुने जाने का अधिकार होता है ? इस प्रक्रिया ने देश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास और प्रोन्नति में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ?

Under what circumstances, apart from concerned parties, a third party has locus standi to move writ petition before the High Court or Supreme Court ? How has this procedure helped in developing and promoting democratic principles in the country ? *20*

(b) भारत के संविधान के अधीन प्रदत्त राज्य के राज्यपाल की शक्तियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । आप निम्नलिखित उक्ति कि "उप-राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन प्रशासन के सुगमीकारक से अधिक नहीं है" की किस प्रकार व्याख्या करेंगे ?

Critically evaluate the powers of the Governor of a State as provided under the Constitution of India. How would you interpret the following observation that "the role of a Lieutenant Governor is no more than that of a facilitator of administration under the President's control" ? *15*

(c) उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित केसों के प्रकाश में, मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के बीच संबंध के बारे में उच्चतम न्यायालय के मत को स्पष्ट कीजिए । क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि इनमें से किसी एक को दूसरे पर प्रमुखता देने से संविधान की सुसंगति गड़बड़ा जाएगी ? शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, आदि से संबंधित आज के परिदृश्य के संदर्भ में, इस विषय पर टिप्पणी कीजिए ।

Explain the opinion of the Supreme Court of India regarding the relation between the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy in the light of its decided cases. Do you agree with the view that giving primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution ? Comment with reference to the present day scenario relating to education, health, religion, etc. *15*

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए :

Answer the following in about 150 words each : *10×5=50*

(a) "आज अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार का विशाल स्थानांतरण है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख सिद्धांत बंधनकारी नियमों, आरोपित कर्तव्यों और राज्य पर अधिकारों के संप्रदान के द्वारा निरूपित है ।" समालोचनापूर्वक टिप्पणी कीजिए ।

"Today there is a huge shift of the basis of International law though the principal component of International law is represented by binding rules, imposing duties and conferring rights upon the state." Comment critically. *10*

(b) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन 'प्रत्यर्पण संधि' के महत्त्व और प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए । क्या एक ऐसे अपराधी का प्रत्यर्पण करने का राज्य का दायित्व होता है, जिस पर एक पड़ोसी राज्य में राजनीतिक हत्या का आरोप है ? कारण बताइए ।

Evaluate the importance and relevance of 'Extradition Treaty', under International law. Is a state liable to extradite an offender, who has been accused of a political murder in a neighbouring state ? Give reasons. *10*

(c) युद्ध-बंदियों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि की प्रभाविता पर चर्चा कीजिए ।

Discuss the efficacy of International Humanitarian law in the protection of Prisoners of War. *10*

(d) "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व व्यवस्था और शांति के लिए खतरा है ।" विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए । साथ ही, 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद' शब्द की परिभाषा कीजिए । इस संबंध में विकसित और विकासशील देशों ने कौन-से प्रमुख कदम उठाए हैं ? चर्चा कीजिए ।

"International Terrorism is a threat to world order and peace." Elucidate. Also define the term 'International Terrorism'. What major steps have been taken up by the developed and developing countries in this respect ? Discuss. *10*

(e) 'संधि की संपुष्टि' के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए । साथ ही, संधि की अ-संपुष्टि के परिणामों का परीक्षण कीजिए ।

Explain the principles of 'Ratification of a Treaty'. Also examine the consequences of non-ratification of a treaty. *10*

Q6. (a) हाल में मार्शल द्वीप गणराज्य (आर.एम.आई.) ने भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण तक पहुँचाने वाली वार्ता को सद्भावपूर्वक आगे बढ़ाने के और समापन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है । क्या यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) की अनिवार्य अधिकारिता के अंतर्गत आएगा ? चर्चा कीजिए । साथ ही, भारत द्वारा इस अधिकारिता को चुनौती दिए जाने की संभावना के सम्बन्ध में उल्लेख कीजिए ।

The Republic of Marshall Islands (RMI) recently filed an application against India in the International Court of Justice (ICJ) alleging India's breach of its obligation to pursue in good faith and conclude negotiations leading to nuclear disarmament. Would it fall under the compulsory jurisdiction of ICJ ? Discuss. Also mention about the possibility of challenging this jurisdiction by India. *20*

(b) "मनुष्य की राष्ट्रीयता एक ओर प्रभुत्वसंपन्न राज्य और दूसरी ओर नागरिक के बीच अविच्छिन्न विधिक सम्बन्ध है ।" उपर्युक्त कथन को स्पष्ट कीजिए । साथ ही, 'राष्ट्रीयता', 'दोहरी राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रहीनता' के बीच अंतर का उल्लेख कीजिए ।

"A man's nationality is a continuing legal relationship between the sovereign state on the one hand and the citizen on the other." Explain the above statement. Also mention the difference between 'nationality', 'double nationality' and 'statelessness'. *15*

(c) निम्नलिखित की परिभाषा कीजिए और उनके बीच विभेदन कीजिए :

(i) राज्य को मान्यता और सरकार को मान्यता

(ii) तथ्यत: मान्यता और विधित: मान्यता

साथ ही, 'सामूहिक मान्यता' संकल्पना को स्पष्ट कीजिए ।

Define and distinguish between the following :

(i) Recognition of State and Recognition of Government

(ii) De facto and De jure recognition

Also explain the concept 'Collective recognition'. *15*

Q7. (a) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनों/अभिसमयों/रीतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । साथ ही, 'पारगमन यात्रा' और उसके दुरुपयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन प्रदान किए गए नियमों पर चर्चा कीजिए ।

Critically evaluate the laws/conventions/practices available for the protection and preservation of marine environment under International law. Also discuss the rules provided under International law for 'transit passage' and its abuses. *20*

(b) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान निकालने के विभिन्न शांतिपूर्ण साधनों की चर्चा कीजिए । आज की समस्याओं के संदर्भ में आपके विचार में कौन-सा साधन अधिक व्यवहार्य है ? कारण बताइए ।

Discuss the various peaceful means of resolving International disputes. Which one according to you is more practical in the context of problems of the present day ? Give reasons. *15*

(c) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन 'प्रादेशिक शरण' शब्द का क्या अर्थ है ? इसके प्रमुख घटक क्या हैं ? और यह 'प्रादेशिक संप्रभुता' शब्द से किस प्रकार भिन्न है ? चर्चा कीजिए ।

What is the meaning of the term 'Territorial Asylum', under International law ? What are its major components ? And how is it different from the term 'Territorial Sovereignty' ? Discuss. *15*

Q8. (a) 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (यू.एन.) चार्टर के उन उपबंधों का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए, जो यू.एन. को राष्ट्रों के बीच 'शांति स्थापन' की अपनी प्राथमिक भूमिका के निष्पादन की शक्ति प्रदान करते हैं । यू.एन. के इस प्रकार्य के सम्बन्ध में आपका क्या आकलन है ? इस प्रयोजन के लिए कुछ उपाय या मार्ग-चित्र (रोड-मैप) सुझाइए ।

Critically examine the provisions of the UN Charter which enables the UN to perform its primary role of 'peace keeping' among nations. What is your assessment regarding this function of the UN ? Suggest some measures or a road-map for this purpose. *20*

(b) आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन, 'हाई सी' (महासमुद्र) शब्द का क्या अर्थ नियत किया गया है ? स्पष्ट कीजिए । हाई सी के क्षेत्रों में नाभिकीय परीक्षण की वैधता की दृष्टि से, हाई सी की स्वतंत्रता की संकल्पना के विस्तार पर भी चर्चा कीजिए ।

Under modern International law what meaning has been assigned to the term 'High Sea' ? Explain. Also discuss the scope of the concept of freedom of the High Sea with reference to legality of nuclear test in the areas of High Sea. *15*

(c) "अंतिम विश्लेषण में, केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं ।" टिप्पणी कीजिए । साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध के संदर्भ में रूपांतरण थियोरी पर भी चर्चा कीजिए ।"

"In the ultimate analysis individuals alone are the subjects of International law." Comment. Also discuss the Transformation theory in the context of the relation between International law and Municipal law. *15*

विधि (प्रश्न-पत्र–I)

समय : तीन घण्टे	अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र के लिए विशेष अनुदेश

(कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।

परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, यदि विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

LAW (PAPER–I)

Time Allowed : Three Hours	Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, if specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. *(a)* भारत के संविधान में समाविष्ट 'परिसंघवाद' की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

Explain the concept of 'Federalism' as incorporated in the Indian Constitution. 10

(b) ''संविधान को संशोधित करने हेतु अंगीकृत की गयी प्रक्रिया अद्वितीय है; यह अनम्य नहीं है फिर भी कठिन है।'' स्पष्ट कीजिए।

"The procedure adopted for amending the Constitution is unique; it is not rigid yet difficult." Elaborate. 10

(c) पक्षपात के विरुद्ध नियम उन घटकों पर प्रहार है जो निर्णय तक पहुँचने में अनुपयुक्त प्रभाव डाल सकते हैं। टिप्पणी कीजिए।

The rule against bias strikes at such factors which may improperly influence in arriving at a decision. Comment. 10

(d) 'सर्वोपरि अधिकार' शब्द से आप क्या समझते हैं? वर्तमान के संदर्भ में इसकी सुसंगतता की विवेचना कीजिए।

What do you understand by the term 'Eminent Domain'? Discuss its relevance in the present-day context. 10

(e) संवैधानिक संशोधनों एवं निर्णीत वादों के संदर्भ में 'मौलिक अधिकारों' एवं 'राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों' के बीच सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

Discuss the relationship between 'Fundamental Rights' and 'Directive Principles of State Policy' in the light of the constitutional amendments and decided cases. 10

2. *(a)* विषय एवं भूक्षेत्र के आधार पर संविधान में प्रदत्त केन्द्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों की विवेचना कीजिए।

Discuss the legislative powers of the Union and States as provided in the Constitution on the basis of subjects and territory. 20

(b) संसद् की विधि निर्मित करने की 'अवशिष्ट शक्तियों' की विवेचना कीजिए।

Discuss 'Residuary Powers' of the Parliament to legislate. 15

(c) ''प्रशासनिक नियम निर्माण करने की आवश्यकता प्रत्यायुक्त विधि-निर्माण का अपरिहार्य है।'' टिप्पणी कीजिए।

"The need for administrative rule making entails delegated legislation." Comment. 15

3. *(a)* राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, विशेषकर तब जबकि दो या दो से अधिक राज्य अन्तर्राज्यीय करार का अनुपालन न कर रहे हों।

Briefly enumerate the executive powers of the President, especially when two or more States are involved in non-observance of an inter-State agreement. 15

(b) 99वें संशोधन अधिनियम, 2014 में अन्तर्निहित सिद्धान्त की विवेचना करते हुए देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए।

While discussing the underlying principle of the 99th Amendment Act, 2014, comment on the present system of appointment of judges to the Higher Judiciary in the country. 20

(c) संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यह भी सुस्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार इसने अपनी निष्पक्षता को बनाये रखा है।

Discuss the powers and functions of the Union Public Service Commission. Also explain how it has maintained its impartiality. 15

4. (a) '' 'विधि का नियम (रूल ऑफ लॉ)' कानूनियत के सिद्धान्त पर आधारित है तथा मनमानी करने की शक्ति का प्रयोग करने के विपरीत है।'' विवेचना कीजिए। यह सुस्पष्ट कीजिए कि क्या कारण बताये बिना शक्ति का प्रयोग मनमाना शक्ति का प्रयोग करने के तुल्य है।

"The 'Rule of Law' is based on the principle of legality and is opposed to exercise of arbitrary powers." Discuss. Explain whether failure to give reasons amounts to exercising power arbitrarily. 20

(b) व्यापारिक निकायों की प्रचुरोद्भवता के परिणामस्वरूप प्रशासनिक त्रुटियों से व्यक्ति के अधिकारों में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन प्रशासनिक त्रुटियों को ठीक करने में 'ओम्बुड्समैन' की भूमिका की विवेचना कीजिए।

The role of 'Ombudsman' is to correct the administrative faults which are troubling the rights of a person in view of proliferation of trading entities. Discuss. 15

(c) '' 'पॉलिसी तथा गाइडलाइन थियोरी' की यह पूर्वधारणा है कि अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकार ने न्याय प्रदान कर दिया है।'' विस्तार से विवेचना कीजिए।

" 'The Policy and Guideline Theory' presupposes delivery of justice by quasi-judicial authority." Elaborate it. 15

खण्ड—B / SECTION—B

5. (a) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति एवं इसके आधार की विवेचना कीजिए।

Discuss the nature and basis of International Law. 10

(b) मानव अधिकार संधियों के विशेष संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति की स्थिति की विवेचना कीजिए।

Discuss the status of individual in International Law especially with respect to Human Rights Treaties. 10

(c) वह संधि निरस्त समझी जाती है जो अपने को सम्मिलित किए जाते समय किसी वर्तमान या नई या उभरती हुई अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मानक या 'जस कोजेन्स' के विरोधाभास में है। टिप्पणी कीजिए।

A treaty is void if it conflicts with an existing or new or emerging peremptory norm of International Law or 'jus cogens' at the time of its inclusion. Comment. 10

(d) क्या ऐसी प्रथा की परम्परा, जिसमें एक विशिष्ट उत्सर्ग द्वारा सभी प्रकार के आरक्षणों का निषेध अथवा कुछ या विशेष या विशिष्ट प्रकार के आरक्षणों का निषेध अथवा आरक्षणों का पूर्णतया निषेध है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में बाधक है? विवेचना कीजिए।

Discuss whether the trend of convention providing a special clause prohibiting all kinds of reservations or some or specific or special kind of reservation or prohibiting reservations totally will hinder the growth of International Law. 10

(e) अन्तर्राष्ट्रीय विधि, मान्यता के साक्ष्यिक सिद्धान्त का साक्ष्य है। विवेचना कीजिए।

International Law evidences the evidentiary theory of recognition. Discuss. 10

6. (a) किस प्रकार भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीय विधि का अंग बन गया है, विवेचना कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के मध्य विरोधाभास की स्थिति में इस देश के न्यायालयों द्वारा किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, स्पष्ट कीजिए।

Discuss how International Law becomes part of the law of the land in India. In case of conflict between the International Law and Municipal Law, which one would be applied by the Municipal Courts of this country? Explain. 20

(b) क्या भारत, भारत-यू० के० के पारस्परिक विधिक सहायता करार के तहत एक भारतीय नागरिक, जो कि भारतीय न्यायालय के उसके विरुद्ध कपट तथा मनी लान्डरिंग मामलों में पारित आदेश के बावजूद यू० के० के लिए पलायन कर गया है, के प्रत्यर्पण की माँग कर सकता है? व्याख्या कीजिए।

Can India invoke the India-UK Mutual Legal Assistance Agreement for extraditing an Indian national who has run away to UK in spite of an Indian Court order in respect of fraud and money laundering against him? Explain. 15

(c) अन्तर्राष्ट्रीय मानवता-सम्बन्धी विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के बीच आवश्यक भिन्नताएँ क्या हैं? व्याख्या कीजिए।

What are the essential differences between the International Humanitarian Law and International Human Rights Law? Explain. 15

7. (a) किसी देश के टेरिटोरियल वाटर (जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य शामिल हैं) से होकर 'निर्दोष संचरण के अधिकार' की विधिक स्थिति की विवेचना कीजिए।

Discuss the legal regime of 'right of innocent passage' through the territorial waters (including international straits) of a State. 20

(b) किसी देश की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, जिसमें दो या दो से अधिक देशों की सम्मिलित मग्नतट भूमि भी शामिल है, के परिसीमन से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए।

Discuss the law of delimitation of the continental shelf of a State including the continental shelf common to two or more States. 20

(c) यू० एन० कन्वेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी, 1982 के अध्याधीन स्थापित इन्टरनैशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (आइ० टी० एल० ओ० एस०) के कार्यों, शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

Discuss the functions, powers and jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) established under the UN Convention on the Law of the Sea, 1982. 10

8. *(a)* वादों की सहायता से रूढ़िगत विधि के अन्तर्राष्ट्रीय नियम के घटकों की विवेचना कीजिए।

Discuss the constituent elements of an international rule of customary law with the help of cases. 10

(b) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VI में विशिष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न उपायों का वर्णन सुसंगत केस विधि की सहायता से कीजिए। इस संदर्भ में सुरक्षा परिषद् की भूमिका की भी विवेचना कीजिए।

Discuss, with the help of relevant case law, various methods specifically mentioned under Chapter VI of the UN Charter to resolve international disputes peacefully. Also discuss the role of Security Council in this regard. 20

(c) यू० एन० एफ० सी० सी० सी०, 2015 के अन्तर्गत पेरिस करार में उल्लिखित अन्तिम शब्दों को 195 राष्ट्रों ने एकमत से अंगीकृत किया था। इस करार के अनुसार राष्ट्रीय अवधारित अंशदान (एन० डी० सी०) की सूचना प्रत्येक 5वें वर्ष दी जाएगी तथा यू० एन० एफ० सी० सी० सी० सचिवालय के साथ इसे पंजीकृत किया जाएगा जो कि 'प्रगामी' होगा स्वयं प्रत्येक राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर। फलतः अंशदान 'बाध्यकारी नहीं' है अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत और एक 'नाम एवं अपमान व्यवस्था' या 'नाम एवं प्रोत्साहन योजना' होगी।

इसके आवश्यक गुणों को स्पष्ट करते हुए, इस करार की उपादेयता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

Final words of Paris Agreement under the UNFCCC, 2015 was adopted unanimously by 195 countries. According to this Agreement, Nationally Determined Contributions (NDC) are to be reported every 5 years and are to be registered with UNFCCC Secretariat which will be 'progressive' depending upon the targets set by each country itself and therefore contributions have been made 'non-binding' as a matter of International Law and there will be a 'name and shame system' or 'name and encourage plan'.

After explaining essential features, comment on the effectiveness of such an Agreement. 20

★★★

CS (MAIN) Exam : 2017

वियोज्य *DETACHABLE*

विधि (प्रश्न-पत्र I)

LAW (Paper I)

समय : तीन घण्टे *Time Allowed : Three Hours*	*अधिकतम अंक : 250* *Maximum Marks : 250*

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

कुल **आठ (8)** प्रश्न **दो खंडों** में दिए गए हैं तथा वह **हिन्दी** एवं **अंग्रेजी** दोनों भाषाओं में छपे हुये हैं ।

परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न क्रमांक **1** एवं **5** अनिवार्य हैं । शेष प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनते हुए **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक प्रश्न के अंत में सूचित हैं ।

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में उत्तर लिखना आवश्यक है तथा यह क्यूसीए (Question-cum-Answer) पुस्तिका में निर्दिष्ट जगह पर उल्लेख करना आवश्यक है । प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गये उत्तरों को अंक नहीं दिये जायेंगे ।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किये गये शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तर क्रमिक विन्यास में गिने जायेंगे । नहीं काटे गए प्रश्न के उत्तर को भी गिनती में लिया जायेगा यद्यपि उसके उत्तर आंशिक रूप में दिए गए हों । उत्तर-पुस्तिका में कोई पन्ना या पन्ना के अंश अगर खाली हैं तो उसे/उन्हें स्पष्ट रूप से काट देना जरूरी है ।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are **EIGHT** questions divided in **Two Sections** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Question Nos. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

खण्ड 'A' SECTION 'A'

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में होने चाहिए :
Answer the following in about 150 words each : 10×5=50

1.(a) 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार' के महत्व पर हाल की निर्णयजन्य विधियों का उल्लेख करते हुए, चर्चा कीजिए ।
Discuss the importance of 'Right to life and personal liberty' with reference to recent case laws. 10

1.(b) क्या 'पंथ निरपेक्षता' भारत के संविधान का एक सारभूत लक्षण है ? विनिश्चयित निर्णयज विधि के प्रकाश में स्पष्ट कीजिए ।
Is 'Secularism' an essential feature of the Constitution of India ? Explain in the light of decided case laws. 10

1.(c) संविधान के अंतर्गत, भारत के उच्चतम न्यायालय की दांडिक विषयों में अपीली अधिकारिता की व्याप्ति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।
Elucidate the scope of the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India under the constitution with regard to Criminal matters. 10

1.(d) भारत में न्याय के ट्रिब्यूनलीकरण की परिघटना को स्पष्ट कीजिए ।
Explain the phenomenon of tribunalisation of justice in India. 10

1.(e) संक्षेप में उन आधारों को स्पष्ट कीजिए जिनके अधीन प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ।
Briefly explain the grounds on which administrative actions can be subjected to judicial review. 10

2.(a) राज्य में राज्यपाल की स्थिति क्या होती है ? संविधान के अंतर्गत, राज्यपाल के क्षमाकरण अधिकार का परीक्षण कीजिए । क्या क्षमाकरण अधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है ?
What is the position of the Governor in a State ? Examine the Pardoning Powers of the Governor under the Constitution. Is Pardoning Power, subject to judicial review ? 20

2.(b) स्थानीय शासन में, पंचायत राज संस्था के महत्व की दृष्टि से, क्या आपके विचार में स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए, शैक्षणिक योग्यता विहित करने का विचार अलोकतांत्रिक और असंबद्ध है ?
In view of the importance of Panchayat Raj institution in local governance, do you think the idea of prescribing educational qualification to contest local body election is undemocratic and incoherent ? 15

2.(c) प्रशासनिक निर्णयों में 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' (ऑडी आल्टेराम पार्टेम) नियम के महत्व की व्याख्या कीजिए और उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत 'पश्च विनिश्चयी सुनवाई' प्राकृतिक न्याय के ओदश को प्रभावी ढंग से संतुष्ट कर सकती है ?
Explain the significance of the rule of 'AUDI ALTERAM PARTEM' in administrative decision making and state the circumstances under which 'post decisional hearing' can effectively satisfy the mandate of natural justice. 15

3.(a) संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध पर सांविधानिक उपबंधों का, प्रशासनिक शक्ति के अंतरा-सरकारी प्रत्यायोजन पर विशेष बल देते हुए, मूल्यांकन कीजिए ।
Evaluate the constitutional provisions relating to administrative relation between the Union and the State with special emphasis on inter-governmental delegation of administrative power. 20

3.(b) संसद और राज्य विधान-मंडलों की, उनके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए, व्यक्ति को दंडित करने की उनकी शक्तियों से संबंधित विधि पर चर्चा कीजिए ।

Discuss the law relating to the powers of Parliament and State Legislatures to punish a person for breach of their privileges. 15

3.(c) उन परिस्थितियों की और उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए, जिनके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति 'वित्तीय आपत्काल' की घोषणा कर सकता है ।

Discuss the circumstances under which 'Financial Emergency' can be proclaimed by the President of India and effects thereof. 15

4.(a) क्या आपके विचार में भारत में न्यायिक सक्रियतावाद में वर्तमान प्रवृत्तियां, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्तों, जो कि संविधान के सारभूत लक्षणों में से एक समझा जाता है, के असंगत हैं ?

Do you think the current trends in judicial activism in India are inconsistent with the Principles of Separation of Powers, which is considered to be one of the basic features of the Constitution ? 20

4.(b) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में, निर्वाचन आयोग की शक्तियों और भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

Examine the powers and role of Election Commission of India in conducting free and fair election. 15

4.(c) क्या आप समझते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पित लोकपाल की संस्था भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में पर्याप्त रूप से प्रभावोत्पादी है ? विधायी ढांचे में अपर्याप्तताओं का कथन कीजिए, यदि कोई हो तो ।

Do you think the institution of Lokpal, as envisaged under the Lokpal and Lokayukta Act, 2013, is efficacious enough to curb corruption in India ? State the inadequacies in the legislative framework, if any. 15

खण्ड 'B' SECTION 'B'

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए :

Answer the following in about 150 words each : 10×5=50

5.(a) अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच के संबंध से संबंधित कौन-कौन सी थियोरियां है ? सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।

What are the theories relating to relationship between International Law and Municipal Law ? Elaborate. 10

5.(b) विप्लव और युद्धावस्था की पहचान करने को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं ?

What are the factors that govern the recognition of insurgency and belligerancy ? 10

5.(c) क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अपनी स्वयं की अधिकारिता के निर्धारण की क्षमता है ? निर्णयज विधि के साथ, विवेचना कीजिए ।

Does the International Court of Justice (ICJ) have the competence to determine its own jurisdiction ? Discuss with case law. 10

5.(d) 'विमान अपहरण' की परिभाषा दीजिए और हेग अभिसमय, 1970 के मुख्य उपबंधों की विवेचना कीजिए ।

Define 'hijacking' and discuss the main provisions of the Hague Convention, 1970. 10

5.(e) संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945 के अंतर्गत बल के प्रयोग और संबंधित अपवादों के प्रतिषेध से संबंधित उपबंधों पर टिप्पणी कीजिए ।

Comment on the provisions relating to prohibition of use of force and exceptions thereto under the U. N. Charter, 1945. 10

6.(a) 'खुला समुद्र' को परिभाषित कीजिए । खुला समुद्र पर अभिसमय के उपबंधों की संक्षेप में विवेचना कीजिए । क्या खुले समुद्र में मछली पकड़ने की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त है ?

Define 'high seas'. Discuss in brief the provisions of the convention on high seas. Is freedom of fishing on high seas recognized ? 20

6.(b) वैश्विक अर्थ-व्यवस्था के स्थायित्व को बनाए रखने में, विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) का विवाद निर्धारण निकाय (डी.एस.बी.) एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है । टीका कीजिए ।

The Dispute Settlement Body (DSB) of the World Trade Organisation (WTO) is playing an important role in maintaining the stability of the global economy. Comment. 15

6.(c) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक निपटारे की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए । न्यायिक निपटारे को सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।

Enumerate the various methods of Peaceful Settlement of International disputes. Elaborate on judicial settlement. 15

7.(a) 'मानव पर्यावरण' से आप क्या अर्थ समझते हैं ? मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार में संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

What do you mean by 'human environment' ? Discuss the role of United Nations Organisation (UNO) in protecting and improving the human environment. 20

7.(b) 'राष्ट्रीयता' को परिभाषित कीजिए । राष्ट्रीयता के अर्जन और लोप की क्या रीतियां हैं ? विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता की क्या स्थिति होती है ?

Define 'Nationality'. What are the modes of acquisition and loss of nationality ? What is the position of nationality of married women ? 15

7.(c) संधियों की विधि पर वियाना अभिसमय, 1969 के अंतर्गत उनके संशोधन और परिवर्तन से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए ।

Discuss the provisions relating to amendment and modification of treaties under the Vienna Convention on Law of Treaties, 1969. 15

8.(a) नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि, 2017 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए । क्या आपके विचार में इससे नाभिकीय हथियारों का संपूर्ण विलोपन हो सकता है ?

Explain the main provisions of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 2017. Do you think it can lead to complete elimination of nuclear weapons ? 20

8.(b) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शरण के अधिकार की व्याप्ति की विवेचना कीजिए और 'भूभागीय' एवं 'इतर भूभागीय शरण' की व्याख्या कीजिए ।

Discuss the scope of right of asylum under International Law and explain 'territorial' and 'extra-territorial' asylum. 15

8.(c) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (कनवेंशनों) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के मूल सिद्धान्तों को सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।

Elucidate the fundamental principles of International Humanitarian Law as envisaged under International Conventions. 15

CS (MAIN) EXAM:2018

EGT-P-LAW

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : **तीन** घंटे Time Allowed : **Three** Hours	अधिकतम अंक : **250** Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

*इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हुए हैं ।*

*परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।*

*प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

*There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

*Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.*

*Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.*

The number of marks carried by a question /part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) 'सहकारी परिसंघवाद' एवं 'प्रतियोगी परिसंघवाद' शब्दों से आप क्या समझते हैं ? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत का संविधान 'प्रतियोगी परिसंघवाद' की संकल्पना पर आधारित है, न कि 'सहकारी परिसंघवाद' की संकल्पना पर ?

What do you understand by the terms 'cooperative federalism' and 'competitive federalism' ? Do you agree with the view that the Indian Constitution is based on the concept of 'competitive federalism' and not on the concept of 'cooperative federalism' ? *10*

(b) प्रशासनिक शक्तियाँ/कार्य हमेशा 'विधिसम्मत शासन' के सिद्धान्त के विरोध में नहीं होते हैं । उदाहरण सहित विवेचना कीजिए ।

Administrative powers/actions are not always in conflict with the 'rule of law' principle. Discuss with illustration. *10*

(c) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' की संकल्पना के परिवर्तनशील आयामों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

Critically evaluate the changing dimensions of the concept of 'State' under Article 12 of the Constitution of India. *10*

(d) "नैसर्गिक न्याय एक ऐसा तैयार फार्मूला नहीं है, जिसे सभी परिस्थितियों में कठोर एकरूपता के साथ माना जाए ।" टिप्पणी कीजिए । निर्णयजन्य विधि का उल्लेख कीजिए ।

"Natural justice is not a made to order formula which has to be fitted to all situations with an iron-bound uniformity." Comment. Refer to case laws. *10*

(e) "सरकार के संसदीय स्वरूप के अंगीकरण के साथ अनुच्छेद 53(1) के अधीन निहितकारी खण्ड काफ़ी हद तक निरर्थक हो जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रालय में निहित होती है ।" भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा एवं स्थिति के संदर्भ में, उपर्युक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । यह भी बताइए कि यदि भारत का राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह को नहीं मानता है, तो उसके क्या-क्या परिणाम होंगे ।

"With the adoption of Parliamentary form of government, the vesting clause under Article 53(1) remains to a great extent meaningless, as real executive power lies in the Ministry." Critically examine the above statement in the context of the status and position of the President of India under the Indian Constitution. Also answer, if the President of India does not accept the advice of the Prime Minister, what consequences would follow. *10*

Q2. (a) संविधान में, विशेष रूप से संविधान के अध्याय IV में और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन, परिकल्पित सामाजिक न्याय की संकल्पना का परीक्षण कीजिए ।

Examine the concept of social justice as envisaged in the Constitution, more particularly in Chapter IV of the Constitution and under Article 14 of the Constitution. *20*

(b) सिविल कर्मचारी को पदच्युति, निष्कासन अथवा सेवाओं की श्रेणी में अवनति के विरुद्ध क्या-क्या संवैधानिक रक्षोपाय उपलब्ध हैं ? क्या ये अधिकार सार्वजनिक निगम के किसी कर्मचारी को भी उपलब्ध हैं ? क़ानूनी प्रावधानों तथा निर्णयजन्य विधि का संदर्भ देकर विवेचना कीजिए ।

What are the constitutional safeguards available to a civil servant against dismissal, removal or reduction in rank of services ? Are these rights also available to an employee of a public corporation ? Discuss with reference to statutory provisions and case law. *15*

(c) भारत में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का सर्वोत्तम पद्धति या तरीका क्या होगा ? अपने विचार व्यक्त कीजिए और उनके समर्थन में तर्क दीजिए ।

What would be the best way or method for the appointment of judges in High Courts and the Supreme Court in India ? Give your views and support your views with reasons. *15*

Q3. (a) भारत में स्थानीय निकायों के प्रचालन में क्या-क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं ? क्या यह सफलता की कहानी है या कि कुछ और है ?

What are the major challenges in the functioning of local bodies in India ? Does it talk about success story or something else ? *20*

(b) क्या राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पर आधारित है ? विवेचना कीजिए । असंख्य शक्तियों के इस्तेमाल में, राज्यपाल का 'विवेक' किस चीज़ से गठित होता है ? क़ानूनी प्रावधानों एवं संगत निर्णयजन्य विधि का संदर्भ देकर व्याख्या कीजिए ।

Is the Governor's post dependent on the pleasure of the President ? Discuss. What exactly constitutes the 'discretion' of the Governor while exercising numerous powers ? Explain with reference to statutory provisions and relevant case law. *15*

(c) प्रत्यायोजित विधान की सांविधानिकता की विवेचना कीजिए । प्रत्यायोजित विधान की परिसीमाएँ क्या हैं ? व्याख्या कीजिए ।

Discuss the constitutionality of delegated legislation. What are the limits of delegated legislation ? Explain. *15*

Q4. (a) "वाक् स्वातंत्र्य में अन्तर्निहित प्रेस की स्वतंत्रता नागरिक के वाक् स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य से उच्चतर धरातल पर स्थित नहीं है, और न ही प्रेस को सामान्य नागरिक से भिन्न कोई ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है ।" इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और 'वाक् एवं अभिव्यक्ति' शब्दों के बीच विभेदन भी कीजिए ।

"The liberty of the press implicit in the freedom of speech stands on no higher footing than the freedom of speech and expression of a citizen, and no privilege is attached to the press as such distinct from the ordinary citizen." Explain this statement and also distinguish the term 'freedom of speech and expression' and 'speech and expression'. *20*

(b) "अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य में आपातकाल का अधिरोपण हमेशा से विवाद का विषय रहा है ।" इस पृष्ठपट में, किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा के परिणामों की व्याख्या कीजिए ।

"Imposition of Emergency in a State under Article 356 has always been a matter of controversy." In this backdrop, explain the consequences of proclamation of Emergency in a State. *15*

(c) किन परिस्थितियों में, भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, संबंधित पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्ति, सुने जाने के अधिकार के लिए रिट याचिकाएँ दायर कर सकता है ? ऐसी याचिकाओं की परिसीमाओं का भी उल्लेख कीजिए ।

Under what circumstances, does a third party, apart from concerned parties, have locus standi to move writ petitions before the High Court or the Supreme Court in India ? Also point out the limitations of such petitions. *15*

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) अंतर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत एवं आधुनिक परिभाषाओं के बीच भिन्नताओं की व्याख्या कीजिए । वर्तमान संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि के बढ़ते हुए विषय-क्षेत्र एवं महत्त्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Explain the distinctions between traditional and modern definitions of international law. Critically examine the growing scope and importance of international law in the present context. *10*

(b) "जहाँ प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है वहाँ शरण समाप्त हो जाती है ।" उपर्युक्त कथन का प्रत्यर्पणीय व्यक्तियों और प्रत्यर्पण अपराधों के विशेष संदर्भ में, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

"Where Extradition begins Asylum ends." Critically examine the above statement with special reference to extraditable persons and extradition crimes. *10*

(c) सामान्यत: यह समझा जाता है कि "अधिकार एवं कर्तव्य सहसंबंधी होते हैं" । फिर भी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन का विकास कर्तव्योन्मुख होने की अपेक्षा अधिकारोन्मुख अधिक हुआ है । ऐसा क्यों हुआ है ? विविध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार लिखतों की सहायता से व्याख्या कीजिए । क्या आप 'मानवाधिकार आंदोलन' के बजाय 'मानव कर्तव्य आंदोलन' के विषय में सोच सकते हैं ?

It is generally viewed that "Rights and Duties are correlative". However, the International Human Rights Movement has developed more as rights-oriented than duties-oriented. Why has this happened ? Explain with the help of various International Human Rights instruments. Can you think of a 'Human Duty Movement' instead of a 'Human Rights Movement' ? *10*

(d) 'अंतर्राष्ट्रीय संधि' की परिभाषा दीजिए और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों के बढ़ते हुए महत्त्व की व्याख्या कीजिए । क्या बहुपक्षीय संधि का परिसमापन किया जा सकता है ? यदि हाँ, तो किन आधारों पर ? व्याख्या कीजिए ।

Define 'International Treaty' and explain the growing importance of treaties in Modern International Law. Can a multilateral treaty be terminated ? If so, on what grounds ? Explain. *10*

(e) क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "वैश्वीकरण एक आवश्यक बुराई है" ? आई.एम.एफ. और आई.बी.आर.डी. द्वारा विकासशील देशों, विशेषकर भारत के संदर्भ में, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से चलाई गई सुधार प्रक्रिया की विवक्षाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Do you agree with the statement that "the Globalization is a necessary evil" ? Critically examine the implications of the reform process undertaken by the IMF and IBRD by way of structural adjustment programmes and policies on developing countries, with special reference to India. *10*

Q6. (a) "महाद्वीपीय शेल्फ को तटवर्ती राज्य के भू-खण्ड का प्राकृतिक विस्तारीकरण माना जाता था ।" अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) की संगत निर्णयजन्य विधि की सहायता से, महाद्वीपीय शेल्फ के सीमांकन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

"Continental Shelf was regarded as the natural prolongation of the land mass of the coastal state." Critically examine the Delimitation of the Continental Shelf with the help of relevant case law of the International Court of Justice (ICJ). *20*

(b) अंतर्राष्ट्रीय विवाद की परिभाषा दीजिए । विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा बाध्यकारी समाधान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए । अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान में, ए.डी.आर. विधियों के बढ़ते हुए महत्त्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Define International Dispute. Explain the difference between peaceful settlement of disputes and compulsive settlement of disputes. Critically examine the growing importance of ADR methods in International Dispute settlement. *15*

(c) "प्रमुखत: निषेधाधिकार (वीटो पावर) के कारण सुरक्षा परिषद की सदस्यता लोकतांत्रिक नहीं है । इस दृष्टि से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए तथा अन्य देशों को अधिक सदस्यता दी जानी चाहिए ताकि राष्ट्रों के समुदाय की जनसांख्यिकीय संरचना प्रतिबिंबित हो ।" व्याख्या कीजिए ।

"Membership of the Security Council is not democratic mainly because of its veto power. In view of that, the U.N. Security Council should be expanded and should give more membership to other countries reflecting the demographic composition of the community of nations." Explain. *15*

Q7. (a) "चार जेनेवा कन्वेंशनों (1949) और 1977 के उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉलों के कुछ प्रावधानों ने आज अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के रूढ़िक सिद्धान्तों (जस कोजन्स) का दर्जा प्राप्त कर लिया है ।" क्या आप उपर्युक्त कथन से सहमत हैं ? चार जेनेवा कन्वेंशनों के साझे अनुच्छेद 3 के आलोक में, अपने तर्कों का औचित्य बताइए ।

"Certain provisions of the four Geneva Conventions (1949) and their additional protocols of 1977 have assumed the status of customary principles (jus cogens) of IHL today." Do you agree with the above statement ? Justify your arguments in the light of common Article 3 of the four Geneva Conventions. *20*

(b) अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों के संदर्भ में, आतंकवाद की संकल्पना की व्याख्या कीजिए । आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, प्रभावशाली रणनीति के रूप में, क्या आप प्रति-आतंकवाद (काउण्टर-टेररिज़्म) को तर्कसंगत मानते हैं ? उदीयमान नवीन आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था प्रभावशाली है ? व्याख्या कीजिए ।

Explain the concept of terrorism in the context of current technological developments. Do you justify counter-terrorism as an effective strategy to deal with terrorist activities ? Is the existing international legal regime effective in dealing with emerging new terrorist threats ? Explain. *15*

(c) पेरिस तथा बर्न व्यवस्थाओं (रेजीमों) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए । क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) और कुछ नहीं है, बल्कि केवल पेरिस तथा बर्न कन्वेंशनों की पुनरावृत्ति मात्र है ।" विवेचना कीजिए ।

Explain the differences between Paris and Bern regimes. Do you agree with the statement that "The Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) is nothing, but mere repetition of the Paris and Bern Conventions." Discuss. *15*

Q8. (a) "अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यत: राज्यों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं हितों से संबद्ध है ।" अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों तथा ग़ैर-राज्य निकायों के स्थान के उल्लेख के साथ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

"International law is primarily concerned with Rights, Duties and Interests of States." Critically examine the statement with reference to the place of Individuals and Non-State entities in International law. *20*

(b) क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "1972 की स्टॉकहोम उद्घोषणा से प्रारम्भ होकर पर्यावरण संबंधी अबाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय लिखतों पर निर्भरता बढ़ गई है" ? इस प्रवृत्ति का विकास क्यों हुआ है और क्या ये लिखतें संधियों की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी हुई हैं ? व्याख्या कीजिए ।

Do you agree with the statement that "Beginning with the Stockholm Declaration of 1972, there has been an increased reliance upon non-binding international instruments dealing with environment" ? Why has this trend developed and have these instruments been more useful than treaties ? Explain. *15*

(c) सामान्यतया यह विचार व्यक्त किया जाता है कि "20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र ने शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो कुछ किया, 21वीं शताब्दी में आर्थिक एवं व्यापार संबंधों के लिए विश्व व्यापार संगठन वही भूमिका निभाने जा रहा है" । राज्यों की राजनीतिक संप्रभुता से आर्थिक संप्रभुता की ओर परिवर्तनशील धारणा के संदर्भ में उपर्युक्त कथन पर चर्चा कीजिए ।

It is generally viewed that "What the U.N. did in the 20th century for maintenance of peace and security, the W.T.O. is going to play the same role on economic and trade relations in the 21st century". Discuss the above statement in view of the changing notion of political sovereignty to economic sovereignty of States. *15*

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : **तीन** घंटे Time Allowed : **Three** Hours	अधिकतम अंक : **250** Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हुए हैं ।

परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are ***EIGHT*** questions divided in ***TWO SECTIONS*** and printed both in ***HINDI*** and in ***ENGLISH***.

Candidate has to attempt ***FIVE*** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any ***THREE*** are to be attempted choosing at least ***ONE*** question from each section.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से, केन्द्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित 'सार और तत्त्व' (पिथ और सब्सटैंस) के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए ।

Discuss the doctrine of 'Pith and Substance' relating to the distribution of legislative powers between the Centre and the States with the help of the landmark judicial decisions. *10*

(b) " 'लोकपाल' के पद का उद्देश्य न्याय-निर्णयन करना नहीं है, अपितु प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के अन्वेषण के लिए एक अलग और अनौपचारिक नियमित व्यवस्था (तंत्र) प्रदान करना है ।" भारत में 'लोकपाल' के पद के औचित्य के प्रतिपादन के साथ, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

"The purpose of the office of the 'Lokpal' is not to adjudicate, but to provide regular machinery for investigating grievances against the administration in a discrete and informal manner." Critically examine this statement by providing proper justification of the office of the 'Lokpal' in India. *10*

(c) "नैसर्गिक न्याय को शीघ्रता और निष्पक्षता के साथ देने के लिए 'औडि औल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष को सुनो) नियम अत्यंत नम्य, लचीली और अनुकूलनशील संकल्पना है ।" निर्णयज वाद-विधि की सहायता से कथन का परीक्षण कीजिए ।

" 'Audi alteram partem', rule is a very flexible, malleable and adaptable concept of natural justice to adjust the need for speed and obligation to act fairly." Examine the statement with the help of decided case-law. *10*

(d) "संसदीय-विशेषाधिकारों का मुद्दा संसद और न्यायपालिका के मध्य विवाद और झगड़े की जड़ बना रहा है ।" विनिर्णीत वादों की पृष्ठभूमि में इस कथन का विश्लेषण कीजिए ।

"The issue of Parliamentary-privileges has been a bone of contention and conflict between the Parliament and the Judiciary." Analyse this statement in the backdrop of decided cases. *10*

(e) "निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के एक अंतर्भूत अंग के रूप में संरक्षित है ।" इस कथन का न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (अवकाश प्राप्त) बनाम भारत संघ के निर्णय के आलोक में विशदीकरण कीजिए ।

"Right to Privacy is protected as an intrinsic part of life and personal liberty enshrined under Article 21 of the Constitution of India." Elucidate this statement in the light of the decision of Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India. *10*

Q2. (a) (i) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्रशासनिक अधिकरणों के विशेष उल्लेख के साथ भारत में अधिकरणों के विस्तार पर समीक्षा दीजिए ।

(ii) "भारत में पंचायती राज प्रणाली को पुनरुज्जीवित करना न्यायपालिका पर कार्यभार को कम करने के सहायक के रूप में है ।" टिप्पणी कीजिए ।

(i) Give an overview of the growth of the Tribunals in India with special reference to Administrative Tribunals established under the Administrative Tribunal Act.

(ii) "Revival of the Panchayati Raj system in India is an aid to reduce the workload on the Judiciary." Comment. *20*

(b) "संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति व्यापक तो है, परन्तु असीमित नहीं है ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? विवेचना कीजिए कि क्या आधारिक संरचना के सिद्धान्त ने संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रबलित किया है अथवा नहीं ।

"Power of the Parliament to amend the Constitution is wide, but not unlimited." Do you agree with this statement ? Discuss whether the doctrine of basic structure has reinforced the power of judicial review under the Constitution. *15*

(c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए और इसका अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से विभेद कीजिए ।

Examine the nature of the powers of the High Courts under Article 226 of the Constitution of India and distinguish it from the powers of the Supreme Court under Article 32. *15*

Q3. (a) प्रशासन को प्रत्यायोजित विधान की शक्ति प्रदान करते हुए, सामर्थ्यकारी अधिनियम में अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए । अधिनियम में अधिकथित अनिवार्यताओं के अननुपालन के क्या परिणाम होते हैं ? विनिश्चयित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए ।

While conferring the power of delegated legislation on the administration, the enabling Act may specify the procedural safeguards to be followed in the exercise of the power. What are the consequences of non-compliance with the requirements as laid down in the Act ? Discuss with the help of decided cases. *20*

(b) "भारत का निर्वाचन आयोग भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्तशासी संवैधानिक प्राधिकरण है ।" भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और प्रकार्यों की व्याख्या करते हुए टिप्पणी कीजिए ।

"The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering the election process in India." Comment by explaining the powers and functions of the Election Commission of India. *15*

(c) "इंडिया अर्थात् 'भारत', राज्यों का संघ होगा ।" व्याख्या कीजिए । क्या आपके विचार में भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है ? विनिश्चयित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए ।

"India that is 'Bharat', shall be a Union of States." Explain. Do you think that the Indian Constitution is a Federal Constitution ? Discuss with the help of decided cases. *15*

Q4. (a) 'विधि-शासन' से आपका क्या अभिप्राय है ? विधि-शासन के डायसी के सिद्धान्त का आधारिक तत्त्व यह है कि 'आप कितने भी उच्च हों, विधि आपसे भी ऊपर है' । विनिश्चयित वादों की सहायता से इसकी विवेचना कीजिए ।

What do you mean by the term 'Rule of Law' ? The basic element of Dicey's doctrine of the rule of law is, 'be you ever so high, the law is above you'. Discuss with the help of decided cases. *20*

(b) राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की विवेचना कीजिए । क्या अध्यादेश की विधिमान्यता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ? सुसंगत वाद-विधि को उद्धृत कीजिए ।

Discuss the Ordinance making power of the President. Can the validity of an Ordinance be challenged in the Court of Law ? Cite relevant case-law. *15*

(c) निम्नलिखित कथनों का परीक्षण और व्याख्या कीजिए :

(i) लोक हित मुक़दमेबाज़ी न्यायपालिका की राजनीति को बढ़ावा देने का एक साधन है ।

(ii) न्यायिक सक्रियता के न्यायपालिका पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं ।

Examine and explain the following statements : *15*

(i) Public Interest Litigation is a tool to promote politics of the Judiciary.

(ii) Judicial Activism has both positive and negative impact on the Judiciary.

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) "अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लोपी बिन्दु है ।" व्याख्या कीजिए ।

"International Law is the vanishing point of Jurisprudence." Explain. *10*

(b) राज्य-मान्यता से आपका क्या अभिप्राय है ? मान्यता के विधिक प्रभाव क्या हैं ? तथ्यत: और विधित: मान्यता में विभेदन कीजिए ।

What do you mean by State-Recognition ? What are the legal effects of recognition ? Differentiate between de-facto and de-jure recognition. *10*

(c) स्व-रक्षा के अपने अन्तर्निहित अधिकार के प्रयोग में, राज्यों के द्वारा विधिपूर्ण बलप्रयोग को नियन्त्रित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्या नियम हैं ?

What are the rules of International Law governing the lawful use of force by the States in the exercise of their inherent right of self-defence ? *10*

(d) अन्तर्राष्ट्रीय लोकोपकारी विधि और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के मध्य क्या अन्तर है ?

What is the difference between International Humanitarian Law and International Human Rights Law ? *10*

(e) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के विभिन्न तरीकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए । क्या आप समझते हैं कि समाधान के यह तरीके (ढंग) प्रभावी हैं या कि वर्तमान परिदृश्य में अन्य कोई तरीके (ढंग) की आवश्यकता है ?

Discuss in brief, the various modes of peaceful settlement of international disputes. Do you think that these modes of settlement are effective or is any other mode required in the present scenario ? *10*

Q6. (a) अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि के मध्य सम्बन्धों को विनिर्धारित करने वाली प्रचलित विभिन्न थ्योरियाँ क्या-क्या हैं ? भारत में राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को किस प्रकार लागू किया जाता है ?

What are the various theories prevalent for deciding the relationship between International Law and Domestic Law ? How do the National Courts in India apply the International Law ? *20*

(b) निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए :

(i) निर्दोष मार्ग का सिद्धान्त

(ii) अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उस पर अन्य राज्यों के अधिकार

Briefly explain the following : *15*

(i) Doctrine of Innocent Passage

(ii) Exclusive Economic Zone and the rights of other States thereto

(c) "अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की प्रभाविता राज्यों द्वारा प्रदत्त सहयोग की मात्रा पर निर्भर करती है । यह सहयोग न केवल अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के राज्य-पक्षकार से संबद्ध होता है, बल्कि अपक्षकार राज्य से भी संबद्ध होता है ।" विवेचना कीजिए ।

"The effectiveness of the International Criminal Court depends on the degree of co-operation provided by the States. This co-operation concerns not only the State-party to the International Criminal Court but also the non-party State." Discuss. *15*

Q7. (a) राज्यों की प्रादेशिक अधिकारिता से आप क्या समझते हैं ? क्या आप इस अभिमत से सहमत हैं कि शरण माँगने का अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के अधीन पूर्णत: स्थापित है ? यदि ऐसा है, तो कारणों सहित अपने उत्तर की संपुष्टि कीजिए ।

What do you understand by territorial jurisdiction of States ? Do you agree with the view that Right to Seek Asylum is firmly established under International Human Rights Law ? If so, substantiate your answer with reasons. *20*

(b) परीक्षण कीजिए कि किस दूरी और सीमाओं तक एक संधि, एक तीसरे राज्य, जो संधि का पक्षकार नहीं है, को अधिकार प्रदान कर सकती है और दायित्व आरोपित कर सकती है ।

Examine the extent and limits to which a treaty can confer rights and impose obligations on the third State which is not party to the treaty. *15*

(c) "संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाने वाले मुद्दों, जिन्हें एक राष्ट्र द्वारा अकेले सुलझाया नहीं जा सकता है, को सुलझाने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण मंच के तौर पर नामित किया जाता है ।" इस कथन के आलोक में महासभा के प्रकार्यों पर चर्चा कीजिए ।

"United Nations is designated as the foremost forum to address the issues that transcend the national boundaries, which cannot be resolved by a country alone." In the light of this statement, discuss the functions of the General Assembly. *15*

Q8. (a) निम्नलिखित पर समालोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

(ii) राज्य प्रायोजित आतंकवाद

Write critical notes on the following : *20*

(i) International efforts towards protection and improvement of human environment

(ii) State-sponsored terrorism

(b) व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (सी.टी.बी.टी.) के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए । साथ ही उन कारणों की भी व्याख्या कीजिए कि भारत ने इस संधि को क्यों हस्ताक्षरित नहीं किया है ।

Discuss the main provisions of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT). Also explain the reasons why India has not signed this treaty. *15*

(c) प्रशुल्कों और व्यापार पर साधारण करार (गैट) के ऐतिहासिक उद्‌भव, उद्देश्यों और प्रमुख सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए ।

Explain the historical evolution, objectives and main principles of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). *15*

CS (Main) Exam, 2020

URC-U-LAW

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : **तीन** घंटे *Time Allowed : **Three** Hours*	अधिकतम अंक : **250** *Maximum Marks : **250***

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

*इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हुए हैं ।*

*परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।*

*प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

*There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

*Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.*

*Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.*

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) उद्देशिका में वर्णित उद्देश्य संविधान के उस मूलभूत ढाँचे को समाहित करते हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता । अग्रणी निर्णित वादों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए ।

The goals specified in the Preamble contain the basic structure of the Constitution, which cannot be amended under Article 368 of the Constitution. Analyse this statement in the light of leading decided cases. *10*

(b) न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायिक शक्ति के बीच विभेद कीजिए । संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत उद्भूत वादों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि की व्याख्या कीजिए ।

Make a distinction between judicial review and judicial power. Explain the scope of judicial review with reference to the cases arising under the X^{th} Schedule of the Constitution. *10*

(c) भारत के संविधान के अंतर्गत सर्वोपरि अधिकार के सिद्धांत की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए । निर्णयज विधि की सहायता से इस सिद्धांत की सीमाओं की व्याख्या कीजिए ।

Analyse the relevance of doctrine of eminent domain under the Constitution of India. Explain the limitations of this doctrine with the help of case law. *10*

(d) भारतीय संविधान में उल्लिखित मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध कीजिए । संवैधानिक (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित किए जाने का तर्काधार क्या है ?

Enumerate the list of Fundamental Duties as provided in the Constitution of India. What is the rationale of incorporation of Fundamental Duties under the Indian Constitution through the Constitutional (Forty-second Amendment) Act, 1976 ? *10*

(e) प्रत्यायोजित विधान के न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकार क्या हैं ?
What are the various modes of judicial control of delegated legislation ? *10*

Q2. (a) (i) लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल एवं लोकायुक्त की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए । आपके विचार में लोकपाल कार्यालय अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्रों से बेहतर कैसे है ?

(ii) राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों की व्याख्या कीजिए । परीक्षण कीजिए कि ऐसी शक्तियों पर न्यायिक पुनर्विलोकन का कहाँ तक प्रयोग किया जा सकता है ।

(i) Discuss the powers and functions of the Lokpal and the Lokayukta under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. How do you think the office of Lokpal is better than other anti-corruption mechanisms ?

(ii) Explain the Pardoning Powers of the President. Examine how far the Judicial Review can be exercised over such powers. *20*

(b) "नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे या नहीं, यह निर्धारण करने के लिए अर्ध-न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के बीच का विभेद अब एक अनन्य मानदंड नहीं रहा ।"
इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
"Distinction between quasi-judicial and administrative functions is no longer the exclusive criteria for deciding whether or not the rules of Natural justice apply."
Critically examine this statement. *15*

(c) उदाहरणों की सहायता से सहयोगात्मक संघवाद एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की विवेचना एवं विभेद कीजिए ।
With the help of illustrations, discuss and differentiate, co-operative federalism and competitive federalism. *15*

Q3. (a) भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदत्त संरक्षात्मक विभेद का परीक्षण कीजिए ।
निर्णित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए ।
Examine the scope of protective discrimination offered to persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes under Articles 15 and 16 of the Constitution of India.
Explain with the help of decided cases. *20*

(b) "संघ एवं राज्य के बीच बेहतर सम्बन्धों हेतु भारतीय संविधान का एक संशोधन अभी बाकी है ।" इस कथन पर टिप्पणी कीजिए एवं इससे सम्बन्धित संविधान के विनिर्दिष्ट उपबंधों में संशोधन की यदि कोई आवश्यकता हो, तो अपनी अनुशंसाओं को सिद्ध कीजिए ।
"An amendment of the Constitution of India for better Union and State relations is due." Comment on this statement and substantiate your recommendations for amendment of specific provisions of the Constitution, if any, on this matter. *15*

(c) "राज्यपाल का कार्यालय सुई जनरेस (sui generis) है । राज्यपाल हमारे तंत्र के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के विस्तार में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य नहीं करते । यद्यपि सीमित एवं संवैधानिक सीमाओं के अधीनस्थ, एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं ।" सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए ।

"Governor's office is sui generis. The Governor in our system does not function as constitutional head for the whole gamut of his responsibilities. There is an important area, though limited and subject to constitutional constraints, within which he acts in the exercise of his discretion." Examine this statement in the light of Sarkaria Commission Report. *15*

Q4. (a) (i) क्या स्थानीय निकाय आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने में स्वायत्तता का उपयोग करते हैं ? संबद्ध संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में व्याख्या कीजिए ।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए ।

(i) Do local bodies enjoy autonomy in performing their role in the field of economic development and social justice ? Explain in the light of relevant constitutional provisions.

(ii) Describe the powers and functions of the Union Public Service Commission. *20*

(b) "विधायिका द्वारा किए जाने वाले उच्च एवं बहुआयामी कार्यों के संपादन हेतु संसदीय विशेषाधिकार अत्यंत आवश्यक है ।" विवेचना कीजिए ।

वर्तमान प्रस्थिति में आप क्या सुधार सुझाना चाहेंगे ?

"Parliamentary privilege is an essential incident to the high and multifarious functions which the legislature performs." Discuss.

What reforms will you suggest, if any, in the existing position ? *15*

(c) "यद्यपि भारत में विधि निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण है, यह न्याय के मूल्य पर नहीं हो सकती है ।"

भारत में "उपचारात्मक रिट याचिका" के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । प्रासंगिक निर्णयज विधि का उल्लेख कीजिए ।

"While certainly law is important in India, it can't be at the cost of justice."

Critically examine this statement in the context of "Curative Writ Petition" in India. Refer to relevant case law. *15*

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को पूरा करने एवं उसे प्रवर्तन में लाने तक कौन-से विभिन्न चरण होते हैं ?

What are the various steps involved for concluding an international treaty and bringing it into force ? *10*

(b) विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य देश "X" उत्पाद "A" पर 7 प्रतिशत प्रशुल्क कम करने के लिए ग़ैर-सदस्य देश "Y" के साथ सहमत होता है । क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश "X" से "A" के सदृश उत्पाद पर उसी समान प्रशुल्क की माँग कर सकते हैं ? विवाद निपटान निकायों ने गैट (GATT) के अनुच्छेद I·1 में "सदृश उत्पाद" को किस प्रकार परिभाषित किया है ?

A WTO member country "X" agrees with a non-member country "Y" to reduce the tariff on product "A" to 7 percent. Can the WTO members claim the same tariff level on like product "A" from country "X" ? How have the dispute settlement bodies defined the "like product" in Article I·1 of GATT ? *10*

(c) संयुक्त राष्ट्र को प्रशासित करने वाले उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए । संयुक्त राष्ट्र प्रणाली हेतु कौन-से सुधार, यदि कोई हों, आप सुझाएँगे ?

Discuss the purposes and principles governing United Nations. What reforms, if any, do you suggest for the UN system ? *10*

(d) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय विवादास्पद अधिकारिता के कौन-से मानदंड हैं ?

What are the parameters of contentious jurisdiction exercisable by the International Court of Justice ? *10*

(e) मानव अधिकार संधियों के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि में मानव की प्रस्थिति की विवेचना कीजिए ।

Discuss the status of individual in International Law especially with reference to human rights treaties. *10*

Q6. (a) संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 67/19 द्वारा फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में ग़ैर-सदस्यी प्रेक्षक राज्य का दर्ज़ा दिए जाने का निर्णय करती है ।

फ़िलिस्तीन के राज्य का दर्ज़ा निर्धारण करने में इस संकल्प के महत्त्व की व्याख्या कीजिए ।

मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों के आलोक में अपने तर्कों का विश्लेषण कीजिए ।

In resolution 67/19, the United Nations General Assembly decides to accord to Palestine, a non-member observer state status in the United Nations.

Explain the importance of the resolution while determining the Statehood of Palestine.

Analyse your arguments in the light of various theories of recognition. *20*

(b) "प्रत्यर्पण जहाँ प्रारम्भ होता है वहीं शरण समाप्त हो जाती है ।" टिप्पणी कीजिए । प्रादेशिक शरण एवं प्रादेशिकेतर शरण में विभेद कीजिए ।

"Asylum ends where extradition begins." Comment. Distinguish between territorial asylum and extra-territorial asylum. *15*

(c) क्या आप इस मत से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल एक सकारात्मक नैतिकता है ? अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति एवं परिधि की विवेचना कीजिए ।

Do you agree with the view that International law is merely a positive morality ? Discuss the nature and scope of International law. *15*

Q7. (a) (i) राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने संबंधी राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं की व्याख्या कीजिए ।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता की भूमिका की व्याख्या कीजिए ।

(i) Explain the State practices relating to observing International law within the Municipal law.

(ii) Explain the role of arbitration for peaceful settlement of international disputes. *20*

(b) भूभागीय समुद्र एवं संलग्न क्षेत्र में तटीय राज्यों तथा अन्य राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की विवेचना कीजिए ।

Discuss the rights and obligations of Coastal States and other States in the territorial waters and contiguous zone. *15*

(c) गैट (GATT) एवं विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अंतर्गत क्षेपण-रोधी प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए । "क्षेपण-रोधी" एवं "वस्तु क्षति" के निर्धारण हेतु क्या पद्धतियाँ बताई गई हैं ?

Explain in detail the anti-dumping provisions under GATT and WTO. What are the methods laid down for determination of "anti-dumping" and "material injury" ? *15*

Q8. (a) अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (IAC) एवं ग़ैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (NIAC) से क्रमश: संबंधित विधिक शासन-प्रणालियों की समझ व परिधि क्या हैं, एवं इन दोनों शासन-प्रणालियों के प्रवर्तन के मूलाधार क्या हैं ?

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संकट पर पड़ने वाले प्रभाव को उदाहरित कीजिए ।

What is the understanding and scope of legal regimes pertaining to International Armed Conflict (IAC) and Non-International Armed Conflict (NIAC) respectively, and what are the thresholds of application of these two regimes ?

Illustrate the impact of International Humanitarian Law on the international refugee crisis. *20*

(b) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधि के मुख्य स्रोतों का मूल्यांकन कीजिए । "मृदु विधि" एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधि के मूल-तत्त्वों के उद्‌भव की विशेषत: व्याख्या और विवेचना कीजिए तथा यह बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस क्षेत्र के विकास को इसने कैसे प्रभावित किया है ।

Evaluate the main sources of International Environmental Law. Explain and discuss in particular the emergence of "Soft Law" and principles of International Environmental Law and how this has influenced the development of this area of International Law. *15*

(c) निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद

(ii) हस्तक्षेप के आधार

(iii) परमाणु अप्रसार संधि

Write notes on the following : *15*

(i) International Terrorism

(ii) Grounds of Intervention

(iii) Nuclear Non-Proliferation Treaty

CS (Main) Exam,2021

HXS-U-LAW

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : **तीन** घंटे Time Allowed : **Three** Hours	अधिकतम अंक : **250** Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

*इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हुए हैं ।*

*परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।*

*प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

*There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

*Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.*

*Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.*

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) "मूल अधिकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने वर्तमान समाज के सामाजिक मूल्यों का संवैधानीकरण कर दिया है ।" दृष्टांत के साथ व्याख्या कीजिए ।

"The Fundamental Rights may be said to constitutionalise social values of existing society." Explain and illustrate. *10*

(b) "भारत में लोकहितवाद न्यायाधीश-नीत (judge-led) तथा वास्तव में कुछ हद तक न्यायाधीश-प्रेरित (judge-induced) है ।" सुसंगत निर्णयज विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए ।

"Public Interest Litigation in India is judge-led and even to some extent judge-induced." Explain with the help of relevant case law. *10*

(c) "शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों एवं मानव अधिकारों का आधार है ।" बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए ।

"Right to Education is the base for the Fundamental Rights and Human Rights." Discuss the efforts made by the Government with regard to Right to Education of the children. *10*

(d) राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए । क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है ? विवेचना कीजिए ।

Explain the relationship between the President and the Council of Ministers. Is the President bound to accept the advice of the Council of Ministers ? Discuss. *10*

(e) भारतीय संविधान के तहत 'विधायी शक्तियों' का प्रत्यायोजन न तो अनुमन्य (प्रदत्त) है और न ही प्रतिषिद्ध है । निर्णीत वादों की सहायता से प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता की विवेचना कीजिए ।

Delegation of 'Legislative Powers' has neither been permitted nor prohibited under the Indian Constitution. Discuss the constitutionality of delegated legislation with the help of decided cases. *10*

Q2. (a) "भारतीय संस्कृति की आधारशिला बहुलवाद (अनेकवाद) है और भारतीय निरपेक्षता का आधार धार्मिक सहिष्णुता है । यह इस विश्वास पर आधारित है कि ईश्वरीय अनुभूति की पूर्णता (सिद्धि) प्राप्त करने के लिए सभी धर्म समान रूप से अच्छे और समर्थ हैं । इस प्रकार, सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है परन्तु यह (अधिकार) आत्यन्तिक नहीं है ।" संवैधानिक उपबंधों एवं सुसंगत निर्णयज विधि की सहायता से उपर्युक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

"Pluralism is the keystone of Indian culture and religious tolerance is the bedrock of Indian Secularism. It is based on the belief that all religions are equally good and efficacious pathways to perfection of God-realisation. Thus, all persons are equally entitled to freedom of religion which is not absolute." Critically examine the above statement with the help of constitutional provisions and relevant case laws. *20*

(b) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया की विवेचना भारत के उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के आलोक में कीजिए । संवैधानिक उपबंधों का भी सन्दर्भ दीजिए ।

Discuss the procedure for the appointment of judges of the Supreme Court and High Courts and transfer of judges of the High Courts in the light of the decisions of the Supreme Court of India. Also refer to the constitutional provisions. *15*

(c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 एवं 257 के उद्देश्य, कार्य और उपयोग की विवेचना कीजिए । क्या इन उपबंधों की पुन:संरचना की जानी चाहिए ? इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों की राज्य द्वारा अवज्ञा किए जाने के क्या परिणाम होते हैं ?

Discuss the purpose, function and use of Articles 256 and 257 of the Constitution of India. Should these provisions be restructured ? What are the consequences of State's defiance of the directives issued under these Articles by the Union ? *15*

Q3. (a) "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हमारे संविधान का 'आधारिक ढाँचा' है और यह लोकतंत्र की 'धड़कन' है ।" किन्तु चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधीकरण ने हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर बना दिया है । चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए ।

"Free and fair election is the 'basic structure' of our Constitution and it is the 'heartbeat' of democracy." But widespread corruption and increasing criminalisation in the election process have made our democracy weak. Discuss the various efforts undertaken by the Election Commission to ensure free and fair election. *20*

(b) "राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' लागू करने के औचित्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रावधान हैं ।" किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा के परिणामों को स्पष्ट कीजिए ।

"Article 356 of the Constitution contains provisions relating to the justification of imposition of 'President's Rule' in the State." Explain the consequences of proclamation of Emergency in a State. *15*

(c) सुसंगत निर्णीत वादों की सहायता से नैसर्गिक न्याय के विभिन्न सिद्धान्तों को समझाइए ।

Explain the various principles of natural justice with the help of relevant decided cases. *15*

Q4. (a) "राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (सिद्धान्तों) के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किन्तु फिर भी वे (तत्त्व) देश के शासन में मूलभूत हैं ।" संविधान के भाग IV में अंकित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त (पूर्ण) करने में सरकार की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

"The provisions of the Directive Principles of State Policy are not enforceable by any court, but they are fundamental in the governance of the country." Critically examine the role of the Government to fulfil the desired objectives enshrined in Part IV of the Constitution. *20*

(b) किसी राज्य में विधिक साक्षरता और महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार के उन्नयन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

Examine the role of State Legal Services Authority in promoting legal literacy and right of women and children in the State. *15*

(c) 'शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त' का क्या तात्पर्य है ? क्या संसदीय प्रणाली की सरकार में इस सिद्धान्त का कठोरता से पालन सम्भव है ? सुसंगत निर्णयज विधियों की सहायता से विवेचना कीजिए ।

What is meant by the 'Doctrine of Separation of Powers' ? Is strict adherence of the doctrine possible under a parliamentary form of government ? Discuss with the help of relevant case laws. *15*

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) 20वीं शताब्दी के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण करने की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए ।

Discuss the various efforts made towards the codification of International Law during the 20th century. *10*

(b) अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों पर विभिन्न सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिए ।

Explain different theories on the relationship between International law and Municipal law. *10*

(c) प्रत्यर्पण की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत 'दोहरी आपराधिकता' का सिद्धान्त तथा 'विशिष्टता का नियम' को स्पष्ट कीजिए ।

Explain the principle of 'Double Criminality' and the 'Rule of Speciality' under the international law of extradition. *10*

(d) 'दोहरी राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रहीनता' को परिभाषित कीजिए । इन्हें समाप्त करने या कम करने के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए ।

Define 'Double Nationality' and 'Statelessness'. Evaluate the efforts taken to eliminate or reduce them. *10*

(e) 'हस्तक्षेप' क्या है और राष्ट्र किन आधारों पर हस्तक्षेप को उचित बताते हैं ? स्पष्ट कीजिए ।

What is 'Intervention' and on what grounds do the States justify intervention ? Explain. *10*

Q6. (a) भेद कीजिए कि 'राज्यों की मान्यता' नीति का एक कृत्य है या विधि का । राज्यों की मान्यता के सृजनात्मक एवं घोषणात्मक सिद्धान्तों में भेद भी बताइए ।

Distinguish whether 'Recognition of States' is an act of policy or of law. Also distinguish between Constitutive and Declaratory theories on the recognition of States. *20*

(b) 'राज्य उत्तराधिकार' से आप क्या समझते हैं ? राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए तथा राज्य उत्तराधिकार से प्रादुर्भूत (उत्पन्न) होने वाले अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट कीजिए ।

What do you understand by 'State Succession' ? Discuss various theories of State succession and explain the rights and obligations arising out of State succession. *15*

(c) समुद्र की विधि की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए । 'क्षेत्रीय (भूभागीय) समुद्र' और 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' की अधिकारिता में क्या अन्तर है ?

Explain the main features of Law of the Sea. What is the difference between the jurisdiction over 'Territorial Sea' and 'Exclusive Economic Zone' ? *15*

Q7. (a) विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने हेतु सुरक्षा परिषद् की शक्तियों की विवेचना कीजिए । सुरक्षा परिषद् द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्या 'वीटो अधिकार' (Veto Power) एक बाधा साबित हुआ है ? स्पष्ट कीजिए ।

Discuss the powers of the Security Council for the maintenance of world peace and security. Has the 'Veto Power' proved a hindrance in discharge of its duties by the Security Council ? Explain. *20*

(b) एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (Economic Order) के साथ-साथ राष्ट्रों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की विवेचना कीजिए ।

Discuss the United Nations Declaration on the establishment of a New International Economic Order along with the Charter of Economic Rights and Duties of States. *15*

(c) "वर्तमान विश्व में मानवता, आतंकवाद के कारण खतरे में है ।" मानवाधिकारों के संबंध में इसकी (मानवता की) रक्षा के उपाय सुझाइए ।

"Humanity is in peril in the present world due to terrorism." Suggest the ways to protect it in the context of human rights. *15*

Q8. (a) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राज्यों का यह विधिक कर्तव्य है कि वे अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करें ? क्या शांतिपूर्ण तरीकों की विफलता राज्यों को अपने विवादों के समाधान के लिए बल प्रयोग करने को अधिकृत कर सकती है ? विवेचना कीजिए ।

Is it a legal duty of States under international law to settle their disputes by peaceful means ? Can failure of peaceful means entitle States to use force to settle their disputes ? Discuss. *20*

(b) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी स्थिति में 'नाभिकीय-अस्त्रों' की धमकी देने या उनके प्रयोग की अनुमति है ? अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा दिए गए सलाहकारी अभिमत के आलोक में प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

Is the threat or the use of 'Nuclear Weapons' in any circumstances permitted under International law ? Answer the question in the light of the advisory opinion given by the International Court of Justice (ICJ). *15*

(c) मानव पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार (अभिवृद्धि) हेतु संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

Discuss the role of United Nations in protection and improvement of human environment. *15*

CIVIL SERVICES (MAIN) EXAM-2022

CRNA-F-LAW

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : **तीन** घंटे Time Allowed : **Three** Hours	अधिकतम अंक : **250** Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हुए हैं ।

परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

*There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

*Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.*

*Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.*

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
Answer the following questions in about 150 words each :

(a) 'पूर्ण समानता स्वयं में असमानता का एक कारण हो सकती है ।' इस कथन के आलोक में, वास्तविक (मौलिक) समानता पर चर्चा कीजिए ।

'Absolute equality may itself be a cause of inequality.' In the light of this statement, discuss substantive equality. *10*

(b) 'बुनियादी स्वतन्त्रताओं और व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान को संविधानवाद के साथ पारगम्य होना चाहिए ।' चर्चा कीजिए ।

'To preserve basic freedoms and dignity of individuals, a Constitution should be permeated with Constitutionalism.' Discuss. *10*

(c) निर्णयज वाद विधियों की सहायता से संघ और राज्य की विधियों के बीच असंगति के सम्बन्ध में विधिक स्थिति की व्याख्या कीजिए । असंगति की स्थिति में कौन-सी विधि अधिभावी होगी ?

Explain the legal position in case of repugnancy between Union and State laws with the help of decided case laws. Which law shall prevail in case of repugnancy ? *10*

(d) स्थानीय निकाय चुनावों में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल के निर्णय में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोटा निर्धारित करने एवं प्रदान करने के लिए कौन-से परीक्षण निर्धारित किए गए हैं ?

What are the tests laid down by the Supreme Court in a recent decision for quantifying and providing quota for Other Backward Classes in local body elections ? *10*

(e) 'वेडनसबरी के अयुक्तियुक्तता के सिद्धान्तों' को स्पष्ट कीजिए । क्या ये सिद्धान्त किसी भी तरह से प्रशासनिक निर्णयों की 'योग्यता-समीक्षा' की गुंजाइश प्रदान करते हैं ?

Elucidate 'Wednesbury's Principles of Unreasonableness'. Do these principles provide in any way, scope for 'merits review' of administrative decisions ? *10*

Q2. (a) "संशोधनकारी शक्ति हमारे संविधान के आधारभूत स्वरूप या संरचना को नुकसान या नष्ट करने तक विस्तारित नहीं होती है ।" चर्चा कीजिए ।

"Amending power does not extend to damaging or destroying the basic structure or framework of our Constitution." Discuss. *20*

(b) संसदीय विशेषाधिकार के मामलों में मूल अधिकारों को लागू करने पर चर्चा कीजिए ।
Discuss the application of fundamental rights to parliamentary privilege cases. *15*

(c) क्या आपको लगता है कि देश के शासन में सभी 'राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व' समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं ? निर्णयज वाद विधियों की सहायता से वर्णन कीजिए ।
Do you think that all the 'Directive Principles of State Policy' are equally fundamental for the governance of the country ? Describe with the help of decided case laws. *15*

Q3. (a) क्या राज्य के सांविधानिक प्रमुख को वास्तव में संघीय व्यवस्था का मुख्य-केन्द्र कहा जा सकता है ? राज्यपाल की शक्तियों एवं कर्तव्यों के आलोक में व्याख्या कीजिए ।
Can the constitutional head of the State be truly described as the nerve-centre of the federal system ? Explain in the light of powers and duties of the Governor. *20*

(b) प्रत्यायोजित विधान को मूल रूप से अधिकारातीत घोषित करने के क्या आधार हैं ? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए ।
What are the grounds to declare a delegated legislation as substantive ultravires ? Refer case laws. *15*

(c) संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात घोषणा के प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिए ।
Briefly discuss the impact of Proclamation of Emergency under Article 352 of the Constitution. *15*

Q4. (a) संसदीय प्रणाली में यद्यपि सदस्यों के संदर्भ में विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई अलगाव नहीं है, दोनों के बीच कार्यों का पृथक्करण है । प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के आलोक में व्याख्या कीजिए ।
In the Parliamentary system, though there is no separation between the legislature and the executive in terms of personnel, there is separation of functions between the two. Explain in the light of relevant judicial decisions. *20*

(b) क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्राथमिक विधानों की वैधता की जाँच करने के लिए सक्षम हैं ? वाद विधि के आलोक में चर्चा कीजिए ।
Are administrative tribunals competent to examine the constitutional validity of primary legislations ? Discuss in the light of case law. *15*

(c) 'आडी आल्टेरम पार्टेम' के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए । ऐसे कौन-से मामले या परिस्थितियाँ हैं जिनमें नैसर्गिक न्याय के पूर्वोक्त सिद्धान्त को बाहर रखा जा सकता है ?
Explain the significance of 'Audi Alteram Partem'. What are the cases or circumstances in which the aforesaid principle of natural justice can be excluded ? *15*

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

(a) समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को ध्यान में रखते हुए, क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की शास्त्रीय परिभाषा बेमानी हो गई है ?

Keeping in view the growth of International Law in the contemporary era, do you think the classical definition of International Law has become redundant ? *10*

(b) 'वस्तुत:-मान्यता' तथा 'विधित:-मान्यता' में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

Distinguish between 'De-facto' and 'De-jure' Recognition. *10*

(c) राज्यक्षेत्रीय आश्रय और बाह्य-राज्यक्षेत्रीय आश्रय क्या हैं ? समझाइए ।

What are Territorial Asylum and Extraterritorial Asylum ? Explain. *10*

(d) 'राज्यक्षेत्रीय-समुद्र' पर राज्यों के विभिन्न अधिकार क्या हैं ?

What are the various Rights of States over 'territorial-waters' ? *10*

(e) अंतर्राष्ट्रीय विधि में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों के रूप में मध्यस्थता एवं न्यायिक निपटारा के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

Distinguish between Arbitration and Judicial settlement as methods of peaceful settlement of disputes in International Law. *10*

Q6. (a) अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों पर विभिन्न सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Critically examine various theories relating to the relationship between International Law and Municipal Law. *20*

(b) राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए ।

Elaborate various theories of State succession. *15*

(c) राष्ट्रीयता के अर्जन और खोने के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए ।

Discuss various modes of acquisition and loss of Nationality. *15*

Q7. (a) महासभा के विभिन्न कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए ।

Describe the various powers and functions of the General Assembly. *20*

(b) "पैक्टा टर्टिस नेक नोसेन्ट नेक प्रोसन्ट" नियम को सुसंगत वाद विधियों की सहायता से स्पष्ट कीजिए ।

Explain the maxim "Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt" with relevant case laws. *15*

(c) क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार में अग्रिम कार्रवाई (प्रि-एंप्टिव एक्शन) करने का अधिकार शामिल है ?

Does the Right to Self-Defence under International Law include Right to take Pre-emptive Action ? *15*

Q8. (a) विमान की ग़ैर-कानूनी ज़ब्ती के दमन के लिए सम्मेलन के उद्देश्य से एक विमान को 'उड़ान में' (इन फ्लाइट) कब माना जाता है ? राज्य पार्टियों पर उक्त सम्मेलन द्वारा आरोपित दायित्वों का अंकन कीजिए ।

When is an aircraft considered to be 'in flight' for the purposes of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ? Delineate the obligations the said convention imposes on the State parties. *20*

(b) विश्व व्यापार संगठन में निर्णय लेने का सबसे पसंदीदा साधन क्या है ? किन परिस्थितियों में बहुमत वोटों से निर्णय लिया जा सकता है ? किन निर्णयों के लिए सुपर बहुमत वोटों की आवश्यकता होती है ? क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है ? विवेचना कीजिए ।

What is the most favoured means of decision-making at World Trade Organisation ? Under what circumstances can decisions be taken by majority votes ? Which decisions require super majority votes ? Is there a need to reform the decision-making process ? Discuss. *15*

(c) अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि (IHL) के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए ।

Explain the core principles of International Humanitarian Law (IHL). *15*

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : **तीन** घंटे
Time Allowed : **Three** Hours

अधिकतम अंक : **250**
Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हुए हैं ।

परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

*There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

*Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.*

*Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.*

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) "भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) राजनैतिक व्यवस्था द्वारा अनुसरण के लिए अपेक्षित आधारभूत मूल्यों को उपदर्शित करती है ।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ? संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में लिपिबद्ध मूल्यों का संदर्भ देते हुए व्याख्या कीजिए ।

"Preamble of the Indian Constitution is indicative of basic values that the political system is expected to pursue." How far do you agree with the statement ? Explain with the reference to values that have been enshrined in the Preamble of the Constitution. *10*

(b) "भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद मुख्यत: 'नाम मात्र के प्रमुख' के रूप में परिकल्पित है ।" इस विषय पर निर्णीत वादों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए ।

"The office of the President under the Indian Constitution has been designed to be largely that of a 'figurehead'." Explain, with reference to the cases decided on the subject. *10*

(c) "केन्द्र तथा राज्य के बीच शक्ति वितरण में केन्द्र के प्रति स्पष्ट झुकाव परिलक्षित होता है ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? व्याख्या कीजिए ।

"There is an obvious slant in favour of the Centre, in distribution of powers between Centre and States." Do you agree with the statement ? Explain. *10*

(d) "नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पत्थर में नहीं ढाले गए हैं और समग्र न्याय की माँग की दृष्टि से उनमें स्थापित विधि के सिद्धान्तों से विचलन की सदैव संभावना रहती है ।" इस विषय पर विनिश्चित वादों का संदर्भ देकर व्याख्या कीजिए ।

"The principles of natural justice are not cast in stone and there is always a possibility of deviation from stated principles of law in view of overall demands of justice." Explain citing decided cases on the subject. *10*

(e) इस विषय पर निर्णीत वादों का उद्धरण देते हुए प्रशासनिक कार्यवाही के न्यायिक पुनरावलोकन के आधारों की व्याख्या एवं विशदीकरण कीजिए ।

Explain and elucidate the grounds of judicial review for administrative action, by quoting decided cases on the subject. *10*

Q2. (a) "भारत के संविधान में सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों को विशिष्ट प्राथमिकता देते हुए एक तरफ सिविल एवं राजनैतिक अधिकार तथा दूसरी तरफ आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के बीच स्पष्ट अन्तर का प्रावधान किया गया है ।" व्याख्या कीजिए ।

"The Constitution of India has provided for a clear-cut distinction between civil and political rights on the one hand and economic and cultural rights on the other, with a distinct primacy given to civil and political rights." Explain. *20*

(b) "पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक प्रस्थिति प्राप्त है ।" भारतीय संविधान में दी गयी पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के प्राधिकार की परिधि एवं संरचना की व्याख्या कीजिए ।

"Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies have been accorded constitutional status." Explain the ambit and structure of the authority of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies under the Indian Constitution. *15*

(c) "भारत का संविधान सिविल सेवकों को संवैधानिक प्रस्थिति तथा संरक्षण प्रदान करता है ।" भारत में सिविल सेवकों को क्या-क्या संरक्षण सुनिश्चित किए गए हैं ? व्याख्या कीजिए ।

"The Constitution of India provides constitutional status and protection to civil servants." What protections have been secured for civil servants in India ? Explain. *15*

Q3. (a) "चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग के पद में निहित है । अत: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का निर्णायक महत्त्व है ।" अद्यतन न्यायिक विनिश्चयों के संदर्भ में उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

"Superintendence, direction and control of elections is vested in the office of the Election Commission and therefore, the appointment of Election Commissioner is of crucial importance in conducting free and fair elections." Critically examine the above statement with reference to recent judicial decisions. *20*

(b) " 'विधिक-सहायता' समाज के गरीब एवं सीमान्त (हाशिए पर) वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच का मूल यंत्र है ।" इस विषय में संवैधानिक उपबंधों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों की विवेचना एवं विशदीकरण कीजिए ।

" 'Legal-Aid' provides a basic tool for access to justice for poor and marginalized sections of society." Discuss and elucidate the Constitutional provisions and the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987. *15*

(c) "किसी व्यवस्था में 'एमिनेन्ट डोमेन' की शक्ति, लोकतांत्रिक संरचना की शक्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? व्याख्या कीजिए ।

"The strength of the 'eminent domain' is inversely proportional to the strength of democratic structure of any system." Do you agree with this statement ? Explain. *15*

Q4. (a) किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप्प (विराम) हो जाने से आप क्या समझते हैं ? इस बिन्दु पर निर्णीत वादों को उद्धृत करते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

What do you understand by breakdown of constitutional machinery in a State ? Critically examine the powers of the President in imposing President's Rule under Article 356 of the Constitution, by citing decided cases on the point. *20*

(b) लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना के उद्देश्यों तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए । कथित अधिनियम की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए ।

Discuss the objectives of the establishment of Lokpal and Lok Ayukta, and their powers and functions under the Lokpal and Lok Ayuktas Act, 2013. Examine the effectiveness of the said Act. *15*

(c) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है । उचित उदाहरण देते हुए इस विषय पर उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

If at any time, it appears to the President that a critical question of law and fact has arisen, the President can obtain the opinion of the Supreme Court. Discuss the role of the Supreme Court in this matter, by giving suitable examples. *15*

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each : *10×5=50*

(a) "प्रत्यक्षवाद के विजय ने व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय बनाने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय विधि का वस्तु बना दिया ।" उक्त कथन के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति की प्रस्थिति पर टिप्पणी कीजिए ।

"Triumph of Positivism has reduced an individual to be an object of international law rather than a subject of international law." Comment on the status of the individual under international law in the light of the above statement. *10*

(b) 'संलग्न परिक्षेत्र' से आप क्या समझते हैं ? इस विषय पर भारतीय अभ्यास (पद्धति) के संदर्भ में व्याख्या कीजिए ।

What do you mean by 'Contiguous Zone' ? Explain with reference to Indian practices on the subject. *10*

(c) राज्यों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों पर मान्यता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए ।

Explain the impact of recognition on the powers and privileges of the States. *10*

(d) 'संधियों की विधि पर वियना अभिसमय, 1969' के संदर्भ में 'जस कोजेन्स' के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।

Explain the principle of 'Jus cogens' with reference to 'Vienna Convention on Law of Treaties, 1969'. *10*

(e) "अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अपेक्षा यूरोपकेन्द्रित संगठन अधिक है ।" उक्त कथन के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए ।

"International Criminal Court is more of a Eurocentric Organisation than an International Court." Explain the jurisdiction of International Criminal Court in light of the above statement. *10*

Q6. (a) "विधि को स्थायी होना चाहिए, हालाँकि यह स्थिर नहीं रह सकती है, क्योंकि इसे स्थायित्व एवं परिवर्तन की संविरोधी आवश्यकताओं में सामंजस्य बनाना है और तीव्र विकासमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्थायित्व अपघटन के रूप में प्रतीत होता है ।" उपर्युक्त कथन के आलोक में परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं नवीन अंतर्राष्ट्रीय विधि में भेद बतलाइए ।

"Law must be stable, and yet it cannot stand still, as it needs to reconcile the conflicting needs of stability and change and in the fast-developing world, the stability appears to have become the casualty in international law." Differentiate between traditional International Law and new International Law in light of the above statement. *20*

(b) "राज्य अपने भूभाग पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को प्रभाव देने के लिए प्रक्रिया में पर्याप्त लचीलापन दर्शाते हैं ।" इस विषय पर संगत वादों का उद्धरण देते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि के मानकों की स्वीकार्यता की व्याख्या कीजिए ।

"States show considerable flexibility in the procedures, whereby they give effect to the rules of the International Law, within their territory." Explain the acceptability of norms of International Law in India, citing relevant cases on the subject. *15*

(c) 'महाद्वीपीय मग्नतटभूमि (शेल्फ़)' तथा 'अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र' में आप कैसे विभेद करेंगे ? सोदाहरण व्याख्या कीजिए ।

How do you distinguish between 'Continental Shelf' and 'Exclusive Economic Zone' ? Explain giving examples. *15*

Q7. (a) "संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानवता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है ।" संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल किया गया है ? व्याख्या एवं विशदीकरण कीजिए ।

"Preamble of the UN Charter is representative of the aspirations of humanity in ensuring peace and security across the globe." How far have these objectives been achieved by the UN ? Explain and elucidate. *20*

(b) "बहुपक्षीय संधि में आपत्ति, संधि के कुछ प्रावधानों की उस राज्य में प्रयोज्यता के विधिक परिणामों को अपवर्जित या उपांतरित करती है ।" उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों में आपत्तियाँ अनुमन्य हैं ।

"Reservation in multilateral treaty excludes or modifies the legal effect of certain provisions of a treaty in its application to that State." Explain the circumstances under which reservations in treaties are permissible under International Law. *15*

(c) अंतर्राष्ट्रीय विधि में किन परिस्थितियों में 'बल प्रयोग' या 'आक्रमण' अनुमन्य और न्यायसंगत है ?

Under what circumstances is recourse to 'force' or 'aggression' permissible and justifiable under International Law ? *15*

Q8. (a) "डब्ल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन) अपने सदस्यों के बीच करार के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो कि वैश्विक व्यापार का विधिक आधार सृजित करता है ।" नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत डब्ल्यू.टी.ओ. के महत्त्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

"WTO provides a platform for agreements amongst its members which form the legal foundation of global trade." Critically evaluate the importance of WTO in the new international economic order. *20*

(b) "संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को मानव पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है ।" उपर्युक्त कथन के आलोक में मानव पर्यावरण के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालिए ।

"Member States of the UN need to take appropriate action for protecting and improving human environment." In light of the above statement, highlight the major steps of the UN for protecting human environment. *15*

(c) "अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को सीमित करने वाले नियमों का समुच्चय है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि अधिकारों के समुच्चय को सुनिश्चित करना चाहती है जो कि मानवों के मानव के रूप में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं ।" अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के बीच उनके अंतर्वस्तु एवं उद्देश्यों के आधार पर विभेद कीजिए ।

"International Humanitarian Law is a set of rules to limit the effects of armed conflict, whereas International Human Rights Law seeks to ensure a set of rights which are essential for survival of humans as Humans." Distinguish between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in terms of their contents and purposes. *15*

PHKM–U–LAW

विधि (प्रश्न-पत्र–I)

निर्धारित समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए)

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हुए हैं।

परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप में काटा जाना चाहिए।

LAW (PAPER–I)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग *150* शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about *150* words each : 10×5=50

(a) उच्च न्यायालयों से आपराधिक मामलों में आने वाली अपीलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का परीक्षण कीजिए।

Examine the appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to criminal matters.

(b) संसद अथवा किसी राज्य विधायिका को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में ही रहना चाहिए तथा अन्यों के विषयक्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

The Parliament or any State Legislature should keep within the domain assigned to it and not encroach upon the other's subject. Critically examine.

(c) ''प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की सिविल सेवा का सदस्य है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारित करता है।'' क्या इस नियम का कोई अपवाद है? वर्णन कीजिए।

"Every person who is a member of civil service of the Union holds office during the pleasure of the President." Is there any exception to this rule? Describe.

(d) भारतीय संविधान प्रत्यायोजन की अनुमति तो देता है, लेकिन साथ ही मूल विधि से संरेखण एवम् विधायी आशय को सुरक्षित रखने हेतु विशेष प्रतिबन्ध भी आरोपित करता है। दृष्टान्तों की सहायता से परीक्षण कीजिए।

The Indian Constitution permits delegation but imposes specific restrictions to ensure alignment with the Parent Act and protect legislative intent. Examine with illustrations.

(e) ''सुसंगत मूलभूत अधिकार के उल्लंघन में अथवा असंगत होने की सीमा तक ही कोई विधि शून्य होगी।'' निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

"A law is void only to the extent of inconsistency or contravention with the relevant Fundamental Right." Explain with the help of decided cases.

2. *(a)* लोक हित वाद की अवधारणा 'लोकस स्टैन्डी' के नियम का अपवाद है। भारत में अग्रणी वादों की सहायता से इसके विकास, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के सन्दर्भ में विस्तारित कीजिए। इसकी कमियों का भी वर्णन कीजिए।

The concept of Public Interest Litigation is an exception to the rule of 'locus standi'. Elaborate in the light of its evolution, aims and objects in India with the help of leading cases. Also discuss its drawbacks. 20

(b) ''संविधानवाद एक मूल विधि के अन्तर्गत सीमित शासन की अवधारणा है।'' इसके आलोक में, संविधान तथा संविधानवाद की सुस्पष्ट विशेषताओं के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए।

"Constitutionalism is the concept of limited government under a Fundamental Law." In the light of this, differentiate between distinctive features of Constitution and Constitutionalism. 15

(c) भारत में संसदीय शासन-प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् के मध्य सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। सुसंगत संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

Discuss the relationship between the President and the Council of Ministers under the parliamentary form of government in India. Explain with the help of relevant constitutional provisions. 15

3. (a) ''अनुच्छेद 194, जो कि अनुच्छेद 105 का सटीक प्रत्युत्पादन है, राज्य विधायिकाओं तथा उनके सदस्यों एवम् समितियों से सम्बन्धित है।'' इस पृष्ठभूमि में टिप्पणी कीजिए कि ये दोनों ही अनुच्छेद एक-दूसरे के पूरक हैं तथा इन्हें साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए।

"Article 194, which is an exact reproduction of Article 105, deals with the State Legislatures and their members and committees." On this background, comment that both the Articles are complementary to each other and should be read together. 20

(b) 'अल्पसंख्यक' कौन हैं? भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों को उस सीमा तक संरक्षित करता है कि उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा प्रशासित करने के प्रदत्त अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं तथा युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के अधीन हैं। निर्णीत वाद विधि की सहायता से विवेचना कीजिए।

Who are 'minorities'? The Constitution of India protects the rights and interests of minorities to the extent that the rights conferred to them to establish and administer educational institutions of their choice are not absolute and are subject to reasonable restrictions. Discuss with the help of decided case laws. 15

(c) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध भी हैं? अपने उत्तर के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के सुसंगत निर्णय भी लिखिए।

Discuss the procedure of amending the Constitution. Are there any restrictions also in this regard? Support your answer with the help of relevant Supreme Court judgments. 15

4. (a) हाल के वर्षों में 'सहकारी संघवाद' की अवधारणा ने राष्ट्र के संवैधानिक शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है, परन्तु साथ ही इसे विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। विस्तारित कीजिए।

In recent years, the concept of 'Cooperative Federalism' has played a pivotal role in constitutional governance of the nation but at the same time it comes across various challenges as well. Elaborate. 20

(b) ''मूलभूत अधिकार अपने आप में साध्य नहीं हैं, बल्कि साध्य के साधन के रूप में हैं। साध्य निदेशक तत्त्वों में विनिर्दिष्ट किया गया है।'' उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए।

"The Fundamental Rights are not an end in themselves but are the means to an end. The end is specified in the Directive Principles." Analyze the statement. 15

(c) "राष्ट्रपति तथा राज्यपालों की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान की एक अनन्य विशेषता है, लेकिन यह व्यावहारिक शासन तथा संभावित अतिसन्धान के बीच धारदार सन्तुलन पर टिकी हुई है।" निर्णीत वाद विधि की सहायता से आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

"The ordinance making power of the President and the Governors is a unique feature of the Indian Constitution but it balances on a razor-sharp edge between pragmatic governance and potential over-reach." Critically examine with the help of decided case laws. 15

खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग *150* शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about *150* words each : 10×5=50

(a) अन्तर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। इसकी कमियों को इंगित कीजिए तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव दीजिए।

Define International Law. Enumerate its weaknesses and give suggestions for improvement.

(b) राज्य मान्यता क्या है? विधितः (डी जुरे) मान्यता तथा वस्तुतः (डी फैक्टो) मान्यता के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए।

What is State recognition? Draw a distinction between recognition de jure and de facto.

(c) राष्ट्रीयता के महत्त्व का परीक्षण कीजिए तथा राष्ट्रीयता के अधिग्रहण के तरीकों का वर्णन कीजिए।

Examine the importance of nationality and discuss the modes of acquisition of nationality.

(d) राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा अन्तर्देशीय जल की अवधारणा के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत राज्यक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई पर टिप्पणी कीजिए।

Distinguish between the concept of territorial sea and inland water. Comment on the breadth of territorial sea that is internationally accepted.

(e) संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग के रूप में 'आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्' के महत्त्व का परीक्षण कीजिए।

Examine the importance of 'the Economic and Social Council' as a principal organ of the United Nations.

6. (a) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध एवम् परस्पर सहयोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों पर विकसित हुआ है। व्याख्या कीजिए।

Peaceful settlement of international disputes has been developed on the principles of International Law concerning friendly relations and cooperations among States. Explain. 20

(b) वर्तमान विश्व 'आर्थिक व्यवस्था', मुक्त बाजार शक्तियों द्वारा संचालित, मुक्त प्रतिस्पर्धा द्वारा उद्वेलित तथा वस्तुओं एवम् सेवाओं के मुक्त संचालन, जिसमें तकनीकी भी सम्मिलित है, पर आधारित उद्यमों द्वारा अनुमित किया जाता है। स्पष्ट कीजिए।

The present world 'Economic Order' is supposed to be granted by the operation of free market forces propelled by free competition and enterprises, based on free movement of goods and services including technology. Elucidate. 15

(c) अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवम् राष्ट्रीय विधि, विधि के एकीकृत ज्ञान की दो शाखाएँ हैं, जो कि मानव समुदाय पर किसी-न-किसी रूप से लागू होती हैं। प्रचलित सिद्धान्तों की सहायता से विस्तारित कीजिए।

International Law and Municipal Law are two branches of unified knowledge of law, which are applicable to human community in someway or the other. Elaborate with the help of prevalent theories. 15

7. (a) 'द्वितीय विश्व युद्ध' में हुए विनाश के उपरान्त विश्व में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित किए जाने हेतु आर्थिक पुनःप्राप्ति को बढ़ावा देने एवम् एक वैश्विक मौद्रिक प्रणाली का निर्माण करने के लिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दो ऐतिहासिक संस्थानों, का अभ्युदय हुआ। विस्तृत वर्णन कीजिए।

Following 'World War II' destruction, the World Bank and the International Monetary Fund emerged as two historic institutions to promote economic recovery and to build a global monetary system to ensure economic stability around the world. Discuss at length. 20

(b) प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि का वर्णन कीजिए। शरण देने की प्रक्रिया और प्रत्यर्पण आवेदन की मंजूरी प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भिन्नता है। व्याख्या कीजिए।

Discuss the law on extradition. The procedure for granting asylum and approving extradition requests differ significantly. Explain. 15

(c) हस्तक्षेप क्या है? मानवीय आधारों पर हस्तक्षेप तथा आत्म-प्रतिरक्षा के कारण हुए हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए।

What is intervention? Discuss the intervention on humanitarian grounds and the intervention due to self-defence. 15

8. (a) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की 'आतंकवाद-विरोधी समिति' के गठन का वर्णन कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आतंकवाद का मुकाबला करने में यह समिति किस सीमा तक प्रभावी रही है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Describe the constitution of United Nations Security Council's 'Counter-Terrorism Committee'. To what extent has this Committee been effective in countering terrorism across international borders? Critically analyze. 20

(b) परमाणु निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या आपकी राय में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (सी० टी० बी० टी०) अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

What do you understand by nuclear disarmament? Do you agree with the opinion that Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) has been successful in achieving its objects? Critically examine. 15

(c) विराष्ट्रिकता क्या है? एक राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति को प्रायः अनेक मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना करना पड़ता है। विराष्ट्रिकता के कारण व्यक्ति को किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? विराष्ट्रिकता से सम्बन्धित मानवाधिकार के मुद्दों को विस्तार से समझाइए।

What is statelessness? A stateless person is often subjected to a number of human rights violation. What are the impediments that people face due to statelessness? Elaborate the human rights issues that are connected to statelessness. 15

★★★